1

बी. एस. यादव और अन्य ई. टी. सी.

वी.

हरियाणा राज्य और अन्य ईटीसी।

5 नवंबर, 1980

[वाई. वी. चंद्रचूड़, सी. जे., पी. एन. भगवती, वी. आर. कृष्णा अय्यर,

वी. डी. तुलजापुरकर और ए. पी. सेन, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 235 और 309, परंतुक-राज्यपाल का दायरा, यदि न्यायिक सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बना सकते हैं

अधिकारी-यदि पूर्वव्यापी रूप से नियमों में संशोधन किया जा सकता है-न्यायिक अधिकारियों की अंतर वरिष्ठता का निर्धारण और यह घोषणा करना कि एक अधिकारी ने परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से स्वीकार किया है, तो राज्यपाल, यदि करने में सक्षम हैं-परिवीक्षा की अवधि को कम किए बिना अलग-अलग मामलों में कम किया जा सकता है।

आवर्तन का नियम, यदि प्रत्यक्ष भर्तियों के कोटा के नियम में पढ़ा जा सकता है और पदोन्नति के लिए खाली पद को बढ़ावा दिया जा सकता है, यदि एक की पुष्टि द्वारा भरा जा सकता है प्रत्यक्ष भर्ती और इसके विपरीत।

कला के प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करना। 309 संविधान (जो राज्यपाल को भर्ती और परिस्थितियों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है)

राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा) पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब उच्च न्यायालय के परामर्श से पंजाब उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963 बनाए। नियमों में पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) से सीधे भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। नियम 8 (2) के तहत संवर्ग पदों की कुल संख्या का दो तिहाई पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और एक तिहाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा संचालित किया जाना है। नियम 10 (1) के तहत सीधी भर्तियों को दो साल के लिए परिवीक्षा पर रहना पड़ता है बशर्ते कि सरकार,

असाधारण परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के परामर्श से परिवीक्षा की अवधि को कम करें। एक अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से दो साल की अवधि से आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन तीन साल की कुल अवधि से अधिक नहीं। नियम 10 (2) राज्यपाल को उच्च न्यायालय के परामर्श से इसकी पुष्टि करने का अधिकार देता है।

एक संवर्ग पद पर सीधी भर्ती उस तारीख से प्रभावी है जिस तारीख को वह परिवीक्षा की अवधि पूरी करता है। नियम 12 (अब हरियाणा में लागू) में प्रावधान है कि सीधी भर्ती और पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता उनकी पुष्टि की संबंधित तिथियों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

9 अप्रैल, 1976 से पूर्वव्यापी रूप से संशोधित पंजाब नियमों के तहत 'कैडर पद' का अर्थ है सेवा में एक स्थायी और साथ ही एक अस्थायी पद। सेवा के सदस्यों की अंतर-वरिष्ठता को पुष्टि की तारीख के बावजूद सेवा में एक पद पर निरंतर सेवा की अवधि से निर्धारित किया जाना है।

हरियाणा रिट याचिकाओं में तीन याचिकाकर्ताओं का चयन एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा राष्ट्र में पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में पुनः नियुक्ति के लिए किया गया था और हरियाणा राज्य के गठन के बाद, उन्हें 1967 और 1968 में हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में कार्यवाहक क्षमता में पदोन्नत किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 3, जो हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती थी, को 7 जुलाई, 10 को जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

बी. एस. यादव बनाम हरियाणा

1970 और 7 जुलाई, 1972 को पूरा होने पर उस पद पर पुष्टि की गई

दो साल की परिवीक्षा अवधि। तीनों याचिकाकर्ताओं की पुष्टि जिला के रूप में की गई

और 8 जुलाई, 1972 से प्रभावी सत्र न्यायाधीश।

पंजाब के न्यायिक अधिकारियों के मामले में, हालांकि दस रिक्तियां थीं

सत्र न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय ने उन रिक्तियों में पदोन्नति की पुष्टि नहीं की लेकिन नियम लागू करके पदोन्नतियों और सीधे भर्ती की पुष्टि की

घूर्णन। छह सीधी भर्तियों को कॉम में पुष्टि की पूर्व तिथियां दी गई थीं।

पदोन्नतियों के साथ पैरिसन, जिसके परिणामस्वरूप आठ की पुष्टि

पदोन्नति स्थगित कर दी गई। कुछ प्रत्यक्ष भर्तियों की पुष्टि के मामले में एक वर्ष और चार महीने की अवधि के भीतर दिया गया था, हालांकि अवधि

परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष थी।

नियम 12 को 9 अप्रैल, 1976 से पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था।

वरिष्ठता का निर्धारण किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि से किया जाना था।

पुष्टि की तारीख की परवाह किए बिना सेवा में।

प्रत्यक्ष भर्तियों में से एक की याचिका को खारिज करते हुए कि नियम न केवल

नियुक्ति के समय कोटा के नियम के आवेदन की आवश्यकता थी लेकिन यह भी

पुष्टि के समय रोटेशन के नियम के आवेदन की आवश्यकता, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियम 8 और 12 एक दूसरे से स्वतंत्र थे, कि

- घूर्णन प्रणाली को प्रदान किए गए कोटा नियम में निहित रूप से नहीं पढ़ा जा सका

नियम 8 द्वारा और उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य इसके हकदार थे

नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से वरिष्ठता का दावा करें। द. पदोन्नतियों ने शिकायत की कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय में

उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक क्षमता का निर्वहन में पालन नहीं किया जा रहा था

इसके प्रशासनिक कर्तव्यों और पदोन्नति और प्रत्यक्ष की वरिष्ठता

भर्तियों को रोटेशन के नियम को लागू किए बिना तय किया जाना चाहिए

पुष्टि करें। यह भी कहा गया था कि 1976 में नियम 12 के संशोधन के बाद

यद्यपि प्रत्येक पर जिला और सत्र न्यायाधीशों की दो रिक्तियां उत्पन्न हुईं

इन अवसरों पर उच्च न्यायालय ने तारीख को देखते हुए एक सीधी भर्ती को बढ़ावा दिया वरिष्ठता के मानदंड के रूप में उनकी पुष्टि।

हरियाणा में पदोन्नति पाने वालों की ओर से यह तर्क दिया गया था कि नियंत्रण

जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय कला के तहत करता है। 235 अधीनस्थ न्यायपालिका पर सेवा की स्थिति को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति शामिल नहीं है।

न्यायिक अधिकारियों की, लेकिन जब से राज्यपाल को इसके तहत शक्ति प्रदान की गई है

न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है कला द्वारा। 235 प्रकृति में अनन्य होने के कारण, इसके संबंध में नियम बनाने की शक्ति

न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता उच्च न्यायालय में होनी चाहिए न कि

राज्यपाल।

पदोन्नति पाने वालों की ओर से यह तर्क दिया गया कि 2 का कोटा: 1

नियम 8 द्वारा प्रदान किया गया प्रावधान केवल प्रारंभिक भर्ती के समय लागू होता है

और उस नियम के आवेदन को बढ़ाने के लिए कोई वारंट नहीं था

पुष्टि का समय।

याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति देना;

पकड़ना: इस तर्क में कोई बल नहीं है कि राज्यपाल के पास नहीं है

जिला और सत्र न्यायाधीशों की वरिष्ठता के नियम बनाने की शक्ति।

6

कला के एक सादे पठन पर। 235 और संविधान का 309 यह स्पष्ट है

कि न्यायपालिका में अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति राज्य की सेवा राज्यपाल में निहित है न कि उच्च न्यायालय में। द.

कला का पहला भाग। 235 जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित करता है

उच्च न्यायालय में। लेकिन उस लेख का दूसरा भाग कहता है कि

लेख में कुछ भी किसी व्यक्ति से छीनने के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित अपील का कोई भी अधिकार जो वह

अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून के तहत या लेखक के रूप में हो सकता है

उसके साथ व्यवहार करने के लिए उच्च न्यायालय का गठन करना अन्यथा के अनुसार

ऐसी कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा की शर्तें। इस प्रकार, कला। 235 स्वयं

जिले पर नियंत्रण की उच्च न्यायालय की शक्ति की बाहरी सीमाओं को परिभाषित करता है।

न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय। सबसे पहले, के अभ्यास में

जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर इसका नियंत्रण इसके लिए खुला नहीं है उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को अस्वीकार करने के लिए

उस कानून द्वारा उसे दिए गए अपील के अधिकार का उल्लेख करें जो शर्त को नियंत्रित करता है।

उनकी सेवाएँ। दूसरा, उच्च न्यायालय अपने आदेश का प्रयोग नहीं कर सकता है। नियंत्रण की शक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ अन्यथा व्यवहार करें

उसकी सेवा की शर्तें जो ऐसी विधि द्वारा विहित हैं। [1052 सी-एफ]

एफ.

द्वारा बनाए गए नियमों के बावजूद उच्च न्यायालय में कानून पारित करने की कोई शक्ति नहीं है।

उच्च न्यायालय उस ओर से उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

कानून की ताकत रखें। विधि जो कला का दूसरा भाग है। 235 की बात करते हैं

विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि। इसलिए, दूसरे का स्पष्ट अर्थ

अनुच्छेद, 235 का भाग यह है कि नियंत्रण की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है

पहला भाग किसी न्यायिक अधिकारी को दिए गए अधिकारों से वंचित नहीं करेगा।

उसकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा। [1052 जी-एच]

अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालयों को ऐसा करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है

जिले से जुड़े न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित नियम

न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय। जब भी इरादा होता है किसी भी प्राधिकारी को कोई विशेष प्रावधान या नियम बनाने की शक्ति प्रदान करना।

संविधान में कहा गया है कि सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों सहित

तो स्पष्ट शब्दों में। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 225 में निहित प्रावधान,

227 (2) & (3) और 229 (1) और (2) उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। कला. 229 (2) जो सीधे बिंदु प्रदान करता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन हो

उच्च न्यायालय के अधिकारियों की सेवा की शर्तें इसके द्वारा बनाई जाएंगी -

उच्च न्यायालय। संविधान के निर्माता विफल नहीं होते कला में एक समान प्रावधान शामिल करें। 235 अगर यह इरादा था कि उच्च

न्यायालयों को शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति होनी चाहिए -

अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की सेवा। [1053 बी-एफ}

अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की शक्ति। 235 स्पष्ट रूप से

उस कानून के अधीन किया गया जिसे राज्य विधानमंडल विनियमित करने के लिए पारित कर सकता है

राज्य के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। फ्रेमर्स

संविधान ने राज्य विधानमंडल की पारित करने की शक्ति को नहीं माना न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में। केवल शक्तियाँ

इस तरह का कानून पारित करना उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण का उल्लंघन नहीं है।

राज्य न्यायपालिका पर। [1053 एच; 1054 सी]

ताकि एक कानून के पारित होने तक कोई वैक्यूम न हो

इस विषय पर विधानमंडल ने संविधान के तहत प्रावधान किया है अनुच्छेद, 309 का परंतुक कि जब तक राज्य विधानमंडल 10 पर एक कानून पारित नहीं करता है

बी. एस. यादव बनाम हरियाणा

विशेष विषय, यह राज्य के राज्यपाल के लिए सक्षम होगा

को।

राज्य के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाएँ। इस प्रकार परंतुक के तहत राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करने के लिए विधानमंडल सक्षम है लेकिन

तथ्य अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। यह विधायी की विशेषताओं में भाग लेता है, न कि कार्यकारी, शक्ति। यह विधायी शक्ति है। [1054 डी-एफ]

कि राज्यपाल के पास संविधान के तहत विधायी शक्ति है

निर्विवाद। जैसे कला के तहत। 213 राज्यपाल प्रतिस्थापित करता है

विधानमंडल क्योंकि विधानमंडल अवकाश में है इसलिए परंतुक के तहत

कला. 309 वह विधानमंडल के लिए प्रतिस्थापित करता है क्योंकि विधानमंडल ने अभी तक नहीं किया है

इस विषय पर एक उपयुक्त कानून पारित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। [1054 जी और 1055 बी-सी]

यह सच है कि अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति प्रावधान के अधीन है।

संविधान के सिद्धांत लेकिन इस कारण से यह तर्क देना गलत है कि

राज्यपाल की भर्ती और शर्तों को विनियमित करने वाले नियम नहीं बना सकते हैं

राज्य के न्यायिक अधिकारियों की सेवा। सबसे पहले, नियंत्रण की शक्ति

अनुच्छेद 235 के पहले भाग द्वारा उच्च न्यायालयों को स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है उस अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा, की शर्तों को विनियमित करने वाले कानूनों के अधीन

इसके न्यायिक अधिकारियों की सेवा। दूसरा, राज्यपाल, समान रूप से पूर्व

प्रेस को अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा नियम बनाने की शक्ति दी गई है

विषय। [1055 बी-सी]

कला का एक संयुक्त पठन। 235 और 309 परिणाम देगा कि हालांकि

अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है

निजी विधानमंडल और जब तक वह विधानमंडल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं करता है

भर्ती और शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति है राज्य के न्यायिक अधिकारियों की सेवा। विधान-मंडल की शक्ति या

राज्यपाल इस प्रकार विधान बनाने के लिए संविधान के अन्य सभी प्रावधानों के अधीन है।

कला की तरह ट्यूशन। 14 और 16. [1055 डी-ई]

कला का दूसरा भाग। 235 प्रदान करने के लिए विधायी शक्ति को मान्यता देता है

न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए

राज्य। कला का मूल प्रावधान। 309 , इसके परंतुक सहित, तय करता है

शक्ति का स्थान। कला के प्रारंभिक शब्द। 309 आयाम को सीमित करें

उस शक्ति से। [1055 एफ]

वरिष्ठता निस्संदेह सेवा की एक महत्वपूर्ण शर्त है। नियंत्रण

कला के पहले भाग द्वारा उच्च न्यायालय में निहित। 235 इसलिए यह विषय है कि उस अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा परिकल्पित वरिष्ठता को विनियमित करने वाली कोई विधि।

इस तरह का कानून बनाने की शक्ति कला द्वारा निहित है। 309 विधानमंडल में और

जब तक यह कार्य नहीं करता, राज्यपाल में। चाहे वह विधानमंडल हो जो एक पारित करता है

अधिनियम या राज्यपाल जो वरिष्ठता, अंतिम उत्पाद को विनियमित करने वाले नियम बनाता है

कला के दूसरे भाग के अर्थ के भीतर कानून है। 235. के विधानमंडल

पंजाब और हरियाणा ने वरिष्ठता को विनियमित करने वाला कोई अधिनियम पारित नहीं किया है।

प्रभावी राज्य न्यायिक अधिकारियों, दोनों राज्यों के राज्यपालों के पास शक्ति है

कला के परंतुक के तहत उस उद्देश्य के लिए नियम बनाना। 309 कॉन्स्टिटट्यूशन की

ट्यूशन। ऐसे नियम संविधान के प्रावधानों के अधीन हैं और

किसी अधिनियम के प्रावधान जिन पर उपयुक्त विधानमंडल पारित कर सकता है -

विषय। [1055 जी-एच]

विधानमंडल द्वारा पारित कानून या राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम

वरिष्ठता के सामान्य या अमूर्त नियमों को उच्च न्यायालय पर छोड़ दें

अवसर आने पर उन्हें प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में लागू करना। द.

वरिष्ठता पर कानून बनाने की शक्ति अन्य सभी प्रावधानों के अधीन है

संविधान का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जिससे प्रभाव पड़े या नुकसान हो।

कला द्वारा उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के लिए मानसिक। 235. [1056 बी-सी] [1981] 1 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28

यद्यपि विधायिका या राज्यपाल के पास वरिष्ठता को विनियमित करने की शक्ति है।

सामान्य अनुप्रयोग के नियमों को निर्धारित करके न्यायिक अधिकारियों का अधिकार, कि

शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जिससे हस्तक्षेप होगा

कला के पहले भाग द्वारा उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण। 235. एक शब्द में कहें तो, वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले कानून के अनुप्रयोग को उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए,

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण एक मामला है।

जो निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय के नियंत्रण के क्षेत्र में आता है

जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय। उसी कारण से,

हालांकि भर्ती के नियम परिवीक्षा की अवधि के लिए प्रदान कर सकते हैं, प्रश्न

यह कि क्या किसी विशेष न्यायिक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी जांच पूरी कर ली है यह या नहीं एक ऐसा मामला है जो विशेष रूप से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है

तय करने के लिए। [1056 ई-एफ]

न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखना होगा। लेकिन

साथ ही विधायिका या राज्यपाल को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।

कला के तहत उनकी वैध विधायी शक्तियाँ। 309. उस शक्ति के अधीन है संविधान के अन्य सभी प्रावधान जिसका अर्थ है कि शक्ति नहीं कर सकती है

इसका प्रयोग इस तरह से किया जाए जिससे कला का उल्लंघन हो। 14 या 16 या कला के पहले भाग का व्यापक दायरा। 235. चूंकि पावर कॉन

कला द्वारा प्रेरित। 309 निरपेक्ष या अनियंत्रित नहीं है तो इसका परीक्षण करना गलत होगा

उस शक्ति की वैधता उसके संभावित दुरुपयोग पर निर्भर करती है। [1057 ए-बी]

पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय बनाम। हरियाणा राज्य, [1975] 3 एससीआर 365,

भारत संघ बनाम। न्यायमूर्ति एस. एच. शेठ, [1978] 1 एस. सी. आर. 423। , ए. पी. उच्च न्यायालय बनाम

कृष्णमूर्ति, [1979] 1 एस. सी. आर. 26 और बिहार राज्य बनाम मदन मोहन प्रसाद,

[1976] 3 एस. सी. आर. 110, संदर्भित।

नियम 8 जैसा कि इसके शीर्ष से ही पता चलता है, सर्वर की एक अलग शर्त प्रदान करता है।

समय के एक विशिष्ट बिंदु के संदर्भ में, अर्थात् "सेवा में भर्ती"।

नियम की भाषा यह भी इंगित करती है कि इस नियम का संचालन सीमित है।

सेवा में प्रारंभिक भर्ती के चरण तक या तो पदोन्नति द्वारा या द्वारा

बार से सीधी नियुक्ति। [1063 एफ]

नियम 8 द्वारा अनुध्यात आरक्षण का उद्देश्य इस पर किया जाना है

कुल संख्या का केवल दो तिहाई आरक्षित करके प्रारंभिक नियुक्ति का चरण

संवर्ग में पदोन्नतों के लिए और एक तिहाई सीधी भर्तियों के लिए पद। एक पोस्ट

जो पदोन्नति के कोटे में खाली पड़ता है, उसे कन्फर्म द्वारा दाखिल नहीं किया जा सकता है।

उसमें प्रत्यक्ष भर्ती की पुष्टि नहीं की जा सकती है और न ही वास्तव में किसी प्रवर्तक की पद जो प्रत्यक्ष भर्तियों के कोटे के भीतर हो। [1063 एच]

यदि यह नियम 8 का सही निर्माण है तो द्वारा पुष्टि की विधि

प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों का आवर्तन, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या रिक्ति है

विशेष अधिकारी को सौंपा गया कार्य उस वर्ग के कोटे के अंतर्गत आता है जिसे

वह उस नियम का उल्लंघन करेगा। [1064 बी]

* नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया नहीं है। नियुक्ति की प्रक्रिया

जैसे ही किसी व्यक्ति को शुरू में सेवा में भर्ती किया जाता है या तो पूरा हो जाता है

पदोन्नति या सीधी भर्ती और पुष्टि प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। नियुक्ति "। सेवा में भर्ती "एक ऐसा मामला है जो इसके अंतर्गत आता है।

अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल की शक्ति। 233 जबकि "पुष्टि" की बात है

' कला के तहत उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण। 235. का अधिरोपण नियम 8, जो संबंधित नियमों पर भर्ती के चरण में कोटा तय करता है

इसलिए पुष्टि और वरिष्ठता बुनियादी संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

न्यायिक सेवा को नियंत्रित करने वाली अवधारणाएँ। [1064 सी-डी] Â

बी. एस. यादव वी. हरियाणा

रोटा के नियम को कोटा के नियम में नहीं पढ़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो

2 का अनुपातः 1 भर्ती के चरण में आवेदन करना होगा लेकिन पुष्टि के चरण में प्रासंगिक नियमों की भाषा में आवेदन नहीं किया जा सकता है। [1066 बी]

ए. के. सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ, [1975] 2 एससीआर 979, एन. के. चौहान बनाम।

गुजरात राज्य, [1977] 1 एस. सी. आर. 1037 संदर्भित।

परमजीत सिंह संधू बनाम। राम रखा, [1979] 3 एस. सी. आर. 584 लागू नहीं था।

उच्च न्यायालय में रोटेशन के नियम को लागू करने में उचित नहीं था

उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की पुष्टि का समय जिन्हें पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा उस सेवा में नियुक्त किया गया था। डी. एस. में। अपने प्रशासनिक कार्यों का प्रभार संभालने में उच्च न्यायालय विफल नहीं हो सकता था

पाँच न्यायाधीशों वाली अपनी विशेष पीठ के निर्णय का पालन करें। [1066 सी-डी]

पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय बनाम। हरियाणा राज्य, [1975] 3 एस. सी. आर.

365 , संदर्भित किया गया।

नियमों की उचित व्याख्या पर, पदोन्नति पाने वाले होने के हकदार हैं

उन रिक्तियों में पुष्टि की जाती है जो उनके दो तिहाई कोटे के भीतर उपलब्ध हैं, चाहे एक तिहाई रिक्तियों पर पुष्टि की गई सीधी भर्तियां हों या नहीं। इसी तरह प्रत्यक्ष भर्तियां उन रिक्तियों में पुष्टि की जाने की हकदार हैं जो उनके एक तिहाई कोटे के भीतर उपलब्ध हैं, चाहे दो तिहाई रिक्तियों पर पुष्टि किए गए पदोन्नतियों का कब्जा हो या न हो। [1067 डी-ई]

निष्पक्षता जो कला है। 14 और 16 अभिधारणा यह है कि यदि एक प्रवर्तक अन्य है

पुष्टि के लिए बुद्धिमानी से उपयुक्त और पदोन्नति के कोटे के भीतर आने वाली एक रिक्ति उपलब्ध है जिसमें उसकी पुष्टि की जा सकती है, उसकी पुष्टि तब तक स्थगित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि एक सीधी भर्ती, चाहे वह अभी तक नियुक्त हो या न हो, अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी नहीं कर लेती है और उसके बाद पुष्टि के लिए पात्र हो जाती है। पुष्टि के मामले में इस सिद्धांत को अपनाने से व्यवहार में पदोन्नति पाने वालों को कोई अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। [1067 डी-ई]।

जहाँ तक उत्तरदाता 6,7 और 8 की पुष्टि का संबंध है,

असाधारण परिस्थितियों की अनुपस्थिति जो उनकी दो साल की कम या खराब परिवीक्षा अवधि को उचित ठहराती है, उच्च न्यायालय के तीन उत्तरदाताओं की पुष्टि करने के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, इससे पहले कि वे सामान्य रूप से पुष्टि के लिए देय थे। यह आदेश समान अवसर की गारंटी का स्पष्ट उल्लंघन है।

वास्तव में, याचिकाकर्ताओं द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे और इस कारण से उन्हें अलग रखा जाना चाहिए। [1067 जी-एच]

नियम 10 (1) के परंतुक द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त शक्ति है

पूर्व-दृष्टया बुरा है क्योंकि ऐसी शक्ति सीधे उच्च न्यायालय में अनुच्छेद द्वारा निहित नियंत्रण पर प्रभाव डालती है। 235 संविधान से। यदि कोई भी प्राधिकारी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो वह उच्च न्यायालय है न कि राज्यपाल। अब नियमों का अर्थ यह समझा जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय, न कि सरकार और न ही उसके पास पुष्टि करने की शक्ति है, कि प्रत्यक्ष भर्तियों की परिवीक्षा की सामान्य अवधि दो वर्ष है और जब तक कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के संबंध में असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं, तब तक एक प्रत्यक्ष भर्ती की पुष्टि उस तारीख से पहले की तारीख से नहीं की जा सकती है जिस दिन उसने दो साल की अपनी जांच संतोषजनक रूप से पूरी की है। उच्च न्यायालय किसी भी अवधि को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है अपनी इच्छा और खुशी से दो साल की अवधि को कम करने या कम करने के लिए परिवीक्षा। [1068 बी-ई]

जहां तक पूर्वव्यापी के साथ एक नियम में संशोधन करने की राज्यपाल की शक्ति का संबंध है

प्रभाव, क्योंकि वह कला के प्रावधान के तहत एक विधायी शक्ति का प्रयोग करता है। 309 , उस प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए वह खुला है। लेकिन जिस तारीख से नियम बनाए गए हैं, उस पर 5-6 एस. सी. इंडिया/एन. डी./81 [1981] 1 एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3

या तो नियमों के सामने से या बाहरी साक्षय द्वारा उचित नेक्सिस

नियमों में निहित प्रावधानों के साथ, विशेष रूप से जब पूर्वव्यापी

प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तत्काल मामले में नियम 12 जो था

दिसंबर की अधिसूचना द्वारा 9 अप्रैल, 1976 से पूर्वव्यापी रूप से संशोधित

31 , 1976 अमान्य है क्योंकि ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं दिखाया गया है। [1068 एफ-एच]

मौलिक न्यायनिर्णय: याचिका सं. लिखें। 4228-4230 1978 का

और 1979 का 266।

(संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

वी. एम. तारकुंडे, ओ. पी. मल्होत्रा, के. एन. भट्ट, विजय कुमार

डब्ल्यू. पी. 4228-4230/78 में याचिकाकर्ताओं के लिए वर्मा और आर. सी. कथुरिया।

वाई. एस. चिताले (डॉ.), लाला राम गुप्ता, सी. आर. सोमशेखरन,

याचिकाकर्ताओं के लिए एम. एस. गणेश, पी. एन. जैन और एम. वी. गोस्वामी

डब्ल्यू. पी. 266/79।

एस. एन. काकर, एस. एन. अशरी, आर. एन. सचथी और एम. एन. श्रॉफ

डब्ल्यू. पी. 4228-4230/78 में उत्तरदाता 1.

सोली जे. सोराबजी और हरदेव सिंह डब्ल्यूपी 4228-30 में आर. 2 के लिए

1978 और 266/79।

डब्ल्यू. पी. में आर. आर. 3-11 के लिए एफ. एस. नरीमन, बी. आर. तुली और आर. एस. सोधी

266/79 .

आर. 3 के लिए प्रदीप सिंह, प्रेम मल्होत्रा और आर. एस. मोंगिया

डब्ल्यूपीएस 4228-30/78 और इंटरवेनर।

ए. के. सेन और श्रीमती उर्मिला कपूर डब्ल्यू. पी. 266/79 में आर. 1 के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था चंद्रचूड़, सी. जे.-अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट याचिकाएं

संविधान में दो-आयामी नियंत्रण पर विचार करना शामिल है

इसके विपरीतः सबसे पहले, प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में

और हरियाणा और दूसरा, जिला न्यायालयों पर नियंत्रण के बीच और कला द्वारा उच्च न्यायालय में निहित अधीनस्थ न्यायालय। 235 और शक्ति

राज्यपाल को अनुच्छेद के परंतुक द्वारा प्रदान किया गया। 309 में से भर्ती और शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने के लिए संविधान।

अन्य बातों के साथ-साथ न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा का

राज्य।

हमारे सामने रिट याचिकाओं के दो सेट हैं जिनमें शामिल हैं -

एक भौतिक अंतर को छोड़कर समान अंक जो हम देखेंगे

यह बाद में। 1978 की 4228 से 4230 तक की रिट याचिकाएँ तीन लोगों द्वारा दायर की गई हैं।

हरियाणा राज्य के न्यायिक अधिकारी जो पदोन्नत हैं, अर्थात्

कहने के लिए, जिन्हें राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया था बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

बाइस पदोन्नति, अर्थात, जिन्हें पंजाब सिविल सेवा (जूडी) से पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया था। सियाल शाखा)। उस याचिका के उत्तरदाता 1 और 2 क्रमशः पंजाब राज्य और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हैं। 3 से 11 उत्तरदाताओं को बार से सीधे पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा में नियुक्त किया गया था।

याचिकाकर्ताओं की कुछ अधिक महत्वपूर्ण शिकायतें यह हैं कि

प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए उनकी वरिष्ठता को गलत तरीके से और अन्यायपूर्ण तरीके से उच्च न्यायिक सेवा में उनके कार्यकाल की तारीख की आकस्मिक परिस्थिति पर निर्भर किया जाता है; कि भले ही एक महत्वपूर्ण रिक्ति उपलब्ध हो, उस रिक्ति में एक प्रोन्नति की पुष्टि मनमाने ढंग से और अनिश्चित काल के लिए की जाती है, कि पदोन्नति के साथ व्यवहार किया जाता है

असमान प्रत्यक्ष भर्तियाँः उदाहरण के लिए, एक प्रवर्तक, अपने संतोषजनक प्रदर्शन और एक महत्वपूर्ण रिक्ति की उपलब्धता के बावजूद, जिसमें उसकी पुष्टि की जा सकती है, एक कार्यवाहक क्षमता में तब तक जारी रहता है जब तक कि एक प्रत्यक्ष भर्ती अपनी परिवीक्षा पूरी नहीं कर लेती है और पुष्टि के लिए देय होती है, और यह कि, उच्च न्यायालय उनकी पुष्टि के समय पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच रोटेशन के सिद्धांत को लागू करता है, जब वास्तव में, प्रासंगिक नियम जो कुछ भी प्रदान करते हैं, वह उनकी नियुक्ति के समय कोटा के नियम का आवेदन है।

पदोन्नति पाने वालों की इन शिकायतों को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है

निम्नलिखित तथ्यों का प्रकाशः हरियाणा रिट याचिकाओं में तीन याचिकाकर्ताओं को पंजाब सिविल सेवा में भर्ती के लिए चुना गया था।

उप (न्यायिक शाखा) प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद। उन्हें 1950 में अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। के अधिनियम 3 द्वारा

1966 , हरियाणा राज्य 1 नवंबर को अस्तित्व में आया।

1966. याचिकाकर्ता 1 और 2-श्री बी. एस. यादव और श्री वी. पी. आगर

वाल को हरियाणा में एक कार्यवाहक क्षमता में पदोन्नत किया गया था

उच्च न्यायिक सेवा को 28 जुलाई और 7 अक्टूबर, 1967 को संबंधित रूप से पदोन्नत किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 3 श्री ए. एन. अग्रवाल को इसी तरह पदोन्नत किया गया था।

27 मार्च, 1968 को। प्रत्यर्थी 3, श्री एन. एस. राव जो एक ज्ञापन के रूप में

बार का बेर जिला अटॉर्नी के रूप में काम कर रहा था, नियुक्त किया गया था

से सीधे हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा को

7 जुलाई, 1970। उनके दो साल के परिवीक्षा की सामान्य अवधि समाप्त हो गई।

7 जुलाई, 1972 को लेकिन उनके कन्फर्म के आदेश जारी होने से पहले

उनके खिलाफ 2 अगस्त, 1972 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

उस शिकायत की जांच उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने की थी, जिन्होंने मार्च 1973 की उनकी रिपोर्ट में इसे निराधार माना गया।

प्रतिवादी

3 [1981] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

?

इसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा जिला और सत्र के रूप में पुष्टि की गई थी

30 मार्च, 1973 से प्रभावी न्यायाधीश। दिनांकित अधिसूचना द्वारा 4 मई, 1973 को उस तारीख को 7 जुलाई, 1972 कर दिया गया था।

जिस पर प्रतिवादी 3 ने दो साल का परिवीक्षाधीन पूरा किया

अवधि। उसी अधिसूचना द्वारा, उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि

याचिकाकर्ताओं और दो अन्य को जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया

8 जुलाई, 1972 से प्रभावी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता, जो अधिकारी थे

राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में लगातार कार्य करते हुए

दो या तीन साल पहले के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रत्यर्थी 3 की सीधे उस सेवा में नियुक्ति के लिए, उनका खो दिया

पुष्टि की तारीख आवंटित करके उस पर वरिष्ठता जो

जिस तारीख को उन्होंने अपना प्रोबा पूरा किया था, उससे एक दिन बाद था।

सत्र की अवधि।

(यहाँ एक छोटे से विषयांतर की अनुमति होगी। सरकार ने

हरियाणा का उच्च न्यायालय को अधिकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था

न्यायिक अधिकारी की पुष्टि करें। इसने उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जिसके तहत श्री एन. एस. राव की पुष्टि की गई और उन्हें वापस करने का आदेश पारित किया गया।

वह एक जिला अटार्नी के पद पर था जिसे वह धारण कर रहा था

जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति का समय। राव ने दाखिल किया

के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका

सरकार। उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में उनके प्रत्यावर्तन को रद्द कर दिया अन्य आधार लेकिन यह बहुमत द्वारा आयोजित (एन. एस. राव बनाम। हर राज्य

याना (1) में निहित प्रत्यक्ष भर्ती की पुष्टि करने की शक्ति राज्यपाल और उच्च न्यायालय में नहीं। इसकी एक संविधान पीठ

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को उलट दिया और सर्वसम्मत निर्णय दिया

निर्णय (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम। हर राज्य (2) कि जिला और सत्र न्यायाधीश की पुष्टि करने की शक्ति

वह उच्च न्यायालय में रहता है और राज्यपाल में नहीं)।

पंजाब रिट याचिका में, चुनाव लड़ने वाले दल हैं -

न्यायिक सेवा। याचिकाकर्ता नंबर 1, श्री प्रितपाल सिंह को पदोन्नत किया गया। 12 नवंबर, 1969 को उस सेवा में, जब वे 44 वर्ष के थे।

प्रत्यर्थी 3, श्री जे. एस. सेखों को सीधे उस सर में नियुक्त किया गया था।

1 फरवरी, 1973 को जब वे 41 वर्ष के थे। पूर्ववर्ती,

हालांकि तीन से अधिक उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया

प्रत्यर्थी 3 की नियुक्ति से कई साल पहले, की पुष्टि की गई थी

3 फरवरी, 1975 जो 2 फरवरी, 1975 से एक दिन बाद था। किस तारीख को उत्तरदाता 3 की पुष्टि की गई थी

दो साल की परिवीक्षा। याचिकाकर्ता संख्या 1 की शिकायत यह है कि

स्थायी रिक्ति 23 दिसंबर, 1972 को उपलब्ध थी जिसमें

(1) आईएलआर 1974 पंजाब 121 (एफ. बी.)।

(2) [1975] 3 एस. सी. आर 365

उसकी पुष्टि की जा सकती थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी 3 को अपनी परिवीक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए समय निर्धारित किया और याचिकाकर्ता 1 को पुष्टि की एक मनमाना और कृत्रिम तारीख दी ताकि वह प्रतिवादी 3 से वरिष्ठता में उच्च स्थान पर न हो। पंजाब रिट याचिका में याचिकाकर्ता 1 का मामला अन्य याचिकाकर्ताओं की शिकायत का उदाहरण है। 2 से 6 याचिकाकर्ताओं को जनवरी 1972 और अगस्त 1972 के बीच उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता 7 को अप्रैल 1973 में, याचिकाकर्ता 8 को अगस्त 1974 में, याचिकाकर्ता 11 को 1975 में, याचिकाकर्ता 17 को 1976 में, याचिकाकर्ता 18 को 1977 में और याचिकाकर्ता 21 और 22 को 1978 में पदोन्नत किया गया था। उत्तरदाता 4 और 5 को जनवरी 1973 में सीधे भर्ती किया गया था और फरवरी 1975 में परिवीक्षाधीन अवधि के पूरा होने पर उनकी पुष्टि की गई थी। उनकी पुष्टि कोई अपवाद नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता 2 और 3 श्री अमरजीत चोपड़ा और श्री एच. एस. अहलूवालिया जो थे

16 जनवरी और 21 अगस्त, 1972 को पदोन्नत होने की पुष्टि क्रमशः 6 अगस्त और 7 अगस्त, 1976 को हुई। उत्तरदाता 6 और 7 की पुष्टि के संबंध में पुष्टि की इन तिथियों का महत्व स्पष्ट हो जाता है। सीधे नियुक्त किया गया है

1 और 2 अप्रैल 1975 को उच्च न्यायिक सेवा, उनकी पुष्टि क्रमशः 2 और 5 अगस्त 1976 को की गई थी, जो उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पहले ही थी। याचिकाकर्ता 2 और 3, जिन्हें 6 और 7 प्रत्यर्थियों की प्रत्यक्ष नियुक्ति से लगभग तीन साल पहले उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया गया था, की पुष्टि 6 और 7 अगस्त, 1976 को की गई थी, जो प्रस्ताव 6 और 7 को आवंटित पुष्टि की तारीखों से तीन या चार दिन बाद थी। याचिकाकर्ता 4 से 22 जिनकी उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति की तारीखें अगस्त 1972 और जुलाई 1978 के बीच थीं, 27 फरवरी, 1979 को रिट याचिका दायर किए जाने तक उनकी पुष्टि नहीं हुई थी।

क्या पंजाब और हरियाणा की उच्च न्यायिक सेवाओं के सदस्यों पर लागू होने वाले नियम इस कार्रवाई की गारंटी देते हैं और नियम कितने हद तक मान्य हैं? इन प्रश्नों को तय करने के लिए हमें प्रासंगिक नियमों पर एक नज़र डालने की आवश्यकता है।

पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा में भर्ती और उसके सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तों को समय-समय पर संशोधित "पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1963" द्वारा विनियमित किया जाता है। ये नियम मूल रूप से पंजाब के राज्यपाल द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल को अनुच्छेद के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे। 309. संविधान से। उस परंतुक द्वारा, राज्यपाल को राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्त प्रति पुत्र की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त नियमों के नियम 2,4,8,9,10,11,12 और 14 जो

वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक जहां तक वे सामग्री हैं:

i

नियम 2: परिभाषाएँ। - (1) ' सेवा में नियुक्ति 'का अर्थ है

कैडर पद पर नियुक्ति, चाहे वह स्थायी हो

दुर्लभ या कार्यवाहक आधार पर, या परिवीक्षा पर;

(2) ' 'संवर्ग पद' का अर्थ है सेवा में एक स्थायी पद;

(6) ' 'सेवा के सदस्य' का अर्थ है एक व्यक्ति

((क) जो इनके आरंभ होने से ठीक पहले

नियम, एक संवर्ग पद रखता है, चाहे वह स्थायी हो उपचारी या कार्यवाहक आधार पर, या परिवीक्षा पर; या

(ख) जिसे कैडर पद पर नियुक्त किया जाता है

इन नियमों के प्रावधान;

(7) ' 'पदोन्नत अधिकारी' का अर्थ है एक व्यक्ति

(क) जो प्रत्यक्ष भर्ती नहीं है और कैडर-पद धारण कर रहा है।

चाहे स्थायी, अस्थायी या कार्यवाहक आधार पर या

परिवीक्षा पर, शुरू होने से तुरंत पहले

ये नियम; या

(ख) जिनसे पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया जाता है

पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)।

नियम 4: प्राधिकरण की नियुक्ति। - सभी नियुक्तियाँ

राज्यपाल के परामर्श से सेवा की जाएगी उच्च न्यायालय,

एफ.

नियम 8 सेवा में भर्ती। - (1) के लिए भर्ती

सेवा की जाएगी।

(i) पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक सेवा) से पदोन्नति द्वारा

शाखा); या

((ii) सीधी भर्ती द्वारा। (2) संवर्ग-पदों की कुल संख्या में से दो-तिहाई पद होंगे -

पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और एक तिहाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा नियुक्त:

बशर्ते कि इस उप-नियम में कुछ भी अधिकारी को नहीं रोकेगा

प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्य की नियुक्ति

(न्यायिक शाखा) किसी भी पद पर जिसे प्रत्यक्ष रूप से भरा जाना है

भर्ती, जब तक कि एक सीधी भर्ती नियुक्त नहीं की जाती है।

नियम 9: प्रत्यक्ष भर्तियों की नियुक्ति। - (1) कोई व्यक्ति नहीं।

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए पात्र होगा जब तक कि वह -

((i) 35 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं है।

अगले जनवरी के पहले दिन की आयु

जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गई है; बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

1

((ii) कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या

प्लीडर और उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह के लिए सिफारिश की जाती है

नियुक्ति।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई हो

उप-नियम (1) के तहत नियुक्ति तब तक की जाएगी जब तक कि वह राज्यपाल द्वारा स्थापित चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाता है और अन्य सभी मामलों में नियुक्ति के लिए भी उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

नियम 10: परिवीक्षा।— (1) सेवा में सीधी भर्तियाँ

दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना, जिसे राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है कि यह कुल तीन वर्ष की अवधि से अधिक न हो।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर राज्यपाल

और न ही, उच्च न्यायालय के परामर्श से, किसी संवर्ग-पद पर सीधी भर्ती की पुष्टि कर सकता है, जो उस तारीख से पहले प्रभावी नहीं होगी जिस दिन वह परिवीक्षा की अवधि पूरी करता है।

(3) यदि किसी प्रत्यक्ष भर्ती के कार्य या आचरण में,

राज्यपाल की राय, जो संतोषजनक नहीं थी, वह किसी भी समय, परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के दौरान, यदि कोई हो, उच्च न्यायालय के परामर्श से और कोई कारण बताए बिना, ऐसी सीधी भर्तियों की सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

नियम 11-पदोन्नत अधिकारियों का रूपांतरण। - अगर काम का

एक संवर्ग-पद पर कार्य करने वाले पदोन्नत अधिकारी की राय में

राज्यपाल का, संतोषजनक नहीं होने पर, वह, कार्यावधि के दौरान किसी भी समय, उच्च न्यायालय के परामर्श से,

((i) उसे उसके मूल पद पर लौटा दिया जाए; या

((ii) उसके साथ ऐसे अन्य तरीके से व्यवहार करें जो आवश्यक हो।

उनकी मूल नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार।

नियम 12: वरिष्ठता। सबस्टैन की वरिष्ठता, आपस में,

सेवा के संबंधित सदस्य, चाहे वे पदोन्नत अधिकारियों की सीधी भर्ती हों, उनकी पुष्टि की संबंधित तिथियों के संदर्भ में निर्धारित किए जाएंगे।

बशर्ते कि मूल सदस्यों की वरिष्ठता

पुष्टि की एक ही तारीख वाली सेवा का खनन निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) प्रत्यक्ष भर्तियों के मामले में आयु में अधिक आयु वाले होंगे -

छोटे से वरिष्ठ;

((ii) पदोन्नत अधिकारियों के मामले में, के अनुसार

पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में वरिष्ठता जैसा कि यह उनकी पुष्टि से तुरंत पहले खड़ा था; [1981] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6

((ग) पदोन्नत अधिकारियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के मामले में,

आयु में अधिक आयु का व्यक्ति छोटे से अधिक आयु का होगा।

नियम 14: चयन ग्रेड। -- (1) सेवा के सदस्य

स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से पदोन्नति के लिए पात्र होगा

निम्नलिखित चयन श्रेणी के पद, निर्दिष्ट वेतनमान वाले

उनके खिलाफ: समय पैमाने पर दो चयन श्रेणी के पद

रु. 1800-100-2000 ; और एक निश्चित स्तर पर दो चयन श्रेणी के पद

रुपये का वेतन। 2,250 .

(2) चयन श्रेणी के पदों पर पदोन्नति की जाएगी।

वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों में योग्यता और उपयुक्तता पर

और सेवा का कोई भी सदस्य इस तरह के अधिकार का हकदार नहीं होगा

पदोन्नति।

नियमों के परिशिष्ट ए से पता चलता है कि पंजाब सुपीरियर जुडिशल

सरकार के सचिव, पंजाब, विधायी विभाग; 15 जिले और सत्र न्यायाधीश; और 4 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश।

इन नियमों में समय-समय पर संशोधन किया गया था

उच्च न्यायालय का परामर्श। प्रासंगिक संशोधन ये हैं:

8 फरवरी, 1966 को पंजाब के राज्यपाल ने

अनुच्छेद को परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। 309 संविधान और

इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों ने "पंजाब" की घोषणा की।

उच्च न्यायिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियम, 1966 "। खंड 2 के अनुसार

इन नियमों में से निम्नलिखित परंतुक उप-नियम (1) में जोड़ा गया था

1963 के नियमों का नियम 10:

" बशर्ते कि राज्यपाल असाधारण परिधि में हो सकता है

परिवीक्षा की अवधि "। 31 दिसंबर, 1976 को पंजाब के राज्यपाल ने

अनुच्छेद को परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ। 309 संविधान का

और इस ओर से उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों ने "पंजाब" बनाया।

उच्च न्यायिक सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1976

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ सुलह। ये हैं नियम 9 अप्रैल, 1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। के नियम 2 (2)

1963 नियम, एक 'कैडर पद' को परिभाषित करने के लिए जिसका अर्थ है एक स्थायी पद

सेवा करते हैं। द्वितीय संशोधन नियमों के खंड 2 ने प्रतिस्थापित किया मूल उप-नियम के लिए नियम 2 में निम्नलिखित उप-नियम (2):

" 2 (2) ' 'संवर्ग पद' का अर्थ है एक स्थायी या अस्थायी पद

सेवा "।

} बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

1

1963 के नियमों के नियम 12 में प्रावधान किया गया है कि सेवा के मूल सदस्यों की वरिष्ठता, चाहे वे प्रत्यक्ष भर्ती हों या पदोन्नति अधिकारी, संबंधित तिथियों की पुष्टि के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। उनके दूसरे संशोधन नियमों के उपखंड 3 ने मूल नियम 12 के लिए निम्नलिखित नियम का उल्लेख किया:

" 12. वरिष्ठता। सदस्यों की वरिष्ठता, साथ ही,

नियुक्ति की तारीख की परवाह किए बिना सेवा में एक पद पर उप यह;

बशर्ते कि दो सदस्यों के मामले में

उसी तारीख को उनकी वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

( ) प्रत्यक्ष भर्तियों के मामले में, उम्र में अधिक उम्र का होगा

छोटे से वरिष्ठ;

((ii) प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा भर्ती किया गया सदस्य होगा -

अन्यथा भर्ती किए गए सदस्य से वरिष्ठ; और

((ग) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, वरिष्ठ

नैतिकता का निर्धारण वरिष्ठता के अनुसार किया जाएगा

नियुक्तियों में ऐसे सदस्य जिनसे वे

पदोन्नत किया गया। "

जहाँ तक पंजाब राज्य का संबंध है, नियम इस प्रकार हैं।

चिंतित हैं। हरियाणा राज्य 1 नवंबर, 1966 को 1966 के अधिनियम 3 द्वारा अस्तित्व में आया था। पंजाब सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम,

1963 , नवंबर 1966 तक संशोधित हरियाणा राज्य पर लागू होता है।

राज्यपाल द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के साथ

हरियाणा।

17 मार्च, 1971 को कुछ औपचारिक संशोधन किए गए -

हरियाणा प्रथम संशोधन नियम, 1971 द्वारा 1963 के नियम। 21 अप्रैल, 1972 को हरियाणा के राज्यपाल ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए

संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त और सभी

उस ओर से उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों ने 1963 के नियमों में संशोधन किया

1 अप्रैल, 1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ हरियाणा प्रथम संशोधन नियम, 1972 द्वारा। संशोधन के खंड 3 द्वारा, परिभाषा नियम 2 (2) में "संवर्ग पद" का अर्थ सेवा में स्थायी या अस्थायी पद के रूप में संशोधित किया गया था। 1963 के नियमों के नियम 8 (2)

बशर्ते कि संवर्ग पदों की कुल संख्या, दो-तिहाई होगी पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और एक तिहाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा संचालित। खंड 5

संशोधन ने कुल का प्रावधान करके इस अनुपात को बदल दिया

पदों की संख्या, तीन-चौथाई पदोन्नत अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाएंगे।

और एक-चौथाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा। नियम 12 शासी वरिष्ठता थी

खंड 6 द्वारा उसी तरीके से संशोधित किया गया है जैसे पंजाब में किया गया था, अर्थात, [1981] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3

सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता प्रदान करके, चाहे

प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नत अधिकारी, लंबाई से निर्धारित किए जाएंगे

सेवा में किसी पद पर निरंतर सेवा की तारीख चाहे जो भी हो

पुष्टि की। एक तरफ हम उल्लेख कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष नहीं है विचाराधीन बिंदुओं में प्रासंगिकता, कि 3 दिसंबर, 1976 को

राज्यपाल अपनी संवैधानिक और अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक संशोधन की घोषणा की जिसमें प्रावधान किया गया था कि:

" कोई व्यक्ति नहीं -
((क) जिसके दो से अधिक बच्चे हैं और जिसने खुद को जन्म नहीं दिया है या

स्वयं या उसके जीवनसाथी की नसबंदी की गई है, या

(ख) जिसके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं, वह जन्म नहीं देता है।

दो से अधिक बच्चे न पैदा करने का वचन,

सेवा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

1 अप्रैल, 1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव। 'संवर्ग पद' की परिभाषा नियम 2 (2) में एक बार फिर से "एक स्थायी पद" के अर्थ में संशोधन किया गया।

सेवा "। इसी तरह, नियम 8 (2) में संशोधन किया गया था।

और एक-तिहाई सीधी भर्तियों द्वारा। नियम 12, जो वरिष्ठता से संबंधित है, मूल स्थिति को बहाल करने के लिए भी संशोधन किया गया था

कि सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी पुष्टि की तारीखों का संदर्भ। संक्षेप में, हरियाणा प्रथम

संशोधन नियम, 1977, जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था

पद ', पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच कोटा और नियम वरिष्ठता।

1 नवंबर, 1966 से जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था

एड, पंजाब राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय रहा है और।

हरियाणा ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बुलाया। दो अलग-अलग

इन दोनों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय शायद इसलिए नहीं बनाए गए थे क्योंकि

राज्यों में से किसी एक के संबंध में व्यवहार्यता के विचार और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लेकिन तथ्य यह है कि

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्तियां दी गई हैं उच्च न्यायालय का कार्य कठिन और असहनीय है। मुख्य न्यायाधीश

और दोनों राज्यों के कॉर्नमन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सामना करना पड़ता है

सदस्यों के लिए सेवा नियमों के एक सेट को लागू करने की दुर्दशा के साथ

एक राज्य की उच्च न्यायिक सेवा और पूरी तरह से अलग, बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

और काफी हद तक दूसरे राज्य के नियमों के विपरीत। जैसा कि मामला आज भी है (और हमारा मतलब है कि हम क्या कहते हैं क्योंकि यह नहीं पता कि एक या दूसरा राज्य कब नियमों में संशोधन करेगा और

किस स्तर की पूर्व सक्रियता के साथ) हरियाणा प्रथम संशोधन के तहत

नियम, 1977, 'संवर्ग पद' का अर्थ है सेवा में एक स्थायी पद। हरियाणा में अस्थायी पद कैडर के पद नहीं हैं। पंजाब में, 'कैडर पद' का अर्थ है उच्च न्यायपालिका में स्थायी और अस्थायी दोनों पद। 'संवर्ग पद' की परिभाषा का न्यायिक अधिकारियों के भाग्य और भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पंजाब में, 31 दिसंबर, 1976 को 1963 के नियमों में किए गए संशोधन से पहले, केवल पदोन्नतियों को ही उच्च न्यायिक सेवा में अस्थायी पदों पर नियुक्त किया जाता था। प्रत्यक्ष भर्तियों को अस्थायी पदों पर नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि अस्थायी पद संवर्ग के बाहर थे और प्रत्यक्ष भर्तियों को केवल संवर्ग पदों पर नियुक्त किया गया था, जिसमें वे परिवीक्षाधीन अवधि के पूरा होने पर पुष्टि के हकदार थे। संशोधन के बाद, अस्थायी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नतियों ने उन पदों पर नियुक्ति का अवसर खो दिया, हालांकि एक कार्यवाहक आधार पर। पंजाब रिट याचिका में 9 से 11 उत्तरदाताओं को जुलाई 1977 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के अस्थायी पदों पर सीधे नियुक्त किया गया था।

वरिष्ठता के नियम के संबंध में, जिस स्थिति में यह प्राप्त होता है

दोनों राज्य मूल रूप से अलग हैं: पंजाब में, 31 दिसंबर, 1976 को संशोधित नियम 12 के तहत 9 अप्रैल से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ,

1976 , वरिष्ठता निरंतर सेवा की अवधि से निर्धारित होती है

पुष्टि की तारीख की परवाह किए बिना एक पोस्ट। हरियाणा में नियम 12

जैसा कि यह मूल रूप से खड़ा था, 1 अप्रैल, 1970 से प्रभावी था

परिणामस्वरूप, उच्च न्यायिक में न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता

सेवा का निर्धारण पुष्टि की तारीखों के संदर्भ में किया जाता है। द.

उच्च न्यायालय को अपने नियंत्रण में अधिकारियों के एक समूह से इस आधार पर निपटना पड़ता है कि पुष्टि की तारीख वरिष्ठता का सही मानदंड है।

और अधिकारियों के एक अन्य समूह के साथ, इसके नियंत्रण में भी, आधार पर

कि एक पद में निरंतर कार्यपालन की अवधि की सही परीक्षा है

वरिष्ठता। उच्च न्यायालय जो भी निर्णय लेता है या उसके लिए प्रेरित होता है

पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच विवाद की एक हड्डी आती है। कभी-कभी, प्रशासनिक निर्णय न तो एक वर्ग को संतुष्ट करता है और न ही दूसरे को, जिससे त्रिकोणीय विवाद होता है। अक्सर

उन नियमों में संशोधन जिन्हें अक्सर एक लंबा पूर्वव्यापी दिया जाता है

प्रभाव, सात साल तक, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक [1981] 1 एस. सी. आर. बनाता है।

0

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुश्किल काम। और अगर संशोधन या तो बिना किसी समझौते के किए जाते हैं

निष्पादित करने के लिए नाजुक कार्य क्योंकि यदि यह अपनी राय का पालन करता है, तो यह एसी है पक्षपात का आरोप लगाया जाता है और यदि यह अपना रुख छोड़ देता है, तो उस पर कमजोर होने का आरोप लगाया जाता है

घुटने टेकना और लड़खड़ाना। द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय

तत्काल मामलों में उच्च न्यायालय पर समय-समय पर हमला किया गया है न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा इनमें से किसी एक आधार पर।

यह अनुशासन और अनुशासन की भावना के लिए शायद ही अनुकूल है।

भाईचारा जिसे न्यायपालिका को सक्रिय करना चाहिए। निश्चित रूप से, राज्य

पंजाब और हरियाणा की सरकारें उच्च न्यायालय को बचा सकती थीं। वरिष्ठता के नियमों का एक सामान्य समूह विकसित करके इस दुर्दशा से,

कम से कम राष्ट्रीय एकता के नाम पर। कुछ खास नहीं है।

पंजाब की मिट्टी में और हरियाणा की मिट्टी में कुछ भी नहीं चाहिए

सेवा के बिल्कुल विपरीत नियमों के अनुप्रयोग को उचित ठहराएँ

दोनों राज्यों के न्यायिक अधिकारी। इनमें शामिल क्षेत्र

दर, जो इन कार्यवाही में शामिल हैं, सभी पंजाब की मिट्टी पर फूल गए लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि वरिष्ठता का उनका दावा इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या

वे पंजाब में ही रहे या हरियाणा को आवंटित किए गए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति काफी हद तक विफलता के कारण उत्पन्न हुई है।

राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय को विश्वास में लेने के लिए, जबकि

सेवा के नियमों में संशोधन करना। पंजाब में किए गए संशोधन

3 दिसंबर, 1966 को 9 अप्रैल, 1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ,

नियम 12 शासी वरिष्ठता में संशोधन सहित, में किया गया था

उच्च न्यायालय के विरोध के दांत और वास्तव में, जहाँ तक नियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव का संबंध है, संशोधन किया गया था

उच्च न्यायालय से परामर्श किए बिना। हरियाणा में नियम 12 में संशोधन किया गया।

1 अप्रैल, 1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 1972 में

उच्च न्यायालय की सलाह। उस संशोधन की स्पष्ट दुर्बलता

यह हो सकता है कि इसे किसी के नुकसान के लिए संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और

केवल एक न्यायिक अधिकारी जिसे सीधे सुपीरियर में भर्ती किया गया था न्यायिक सेवा, अर्थात् श्री एन. एस. राव, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 हैं

हरियाणा याचिकाएँ। हालाँकि, मूल नियम 12 को हटा दिया गया था।

राज्य सरकार द्वारा एक और संशोधन द्वारा पुनर्स्थापित किया गया

दिनांक 4 सितंबर, 1977। सरकार में हुआ था बदलाव

जो स्पष्ट रूप से नियमों में बदलाव का कारण बना, जैसे कि सेवा नियम हैं सरकार के हाथों में कुछ भी। यह केवल दिखाता है कि कैसे

के तहत नियम बनाने से पहले उच्च न्यायालय से परामर्श करना संविधान के अनुच्छेद 309 का प्रावधान। परामर्श, चाहे वह कहा गया हो

उच्च न्यायालय से पूछने की औपचारिक प्रक्रिया के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए किसी विशेष मुद्दे पर इसकी क्या राय है।

बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.) से परामर्श लिया जा रहा है।

10

प्रस्तावित कार्रवाई की सार्थक प्रस्तावना, जिसके तहत उच्च न्यायालय को विचाराधीन मामले पर चर्चा करने और प्रस्तावित कार्रवाई के लिए सरकार या राज्यपाल के कारणों को पूरा करने का अवसर दिया जाता है। तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय एक या दूसरे राज्यपाल को अपना दृष्टिकोण देखने के लिए राजी करने का प्रयास कर सकता था; अन्यथा, यह कम से कम दोनों राज्यपालों को दोनों राज्यों के लिए नियमों के एक समान पैटर्न को अपनाने की अनिवार्यता को प्रभावित कर सकता था, जो एक समान उच्च न्यायालय से धन्य हैं।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों की उच्च न्यायिक सेवा

वरिष्ठता क्योंकि समय-समय पर नियमों में संशोधन किया जा रहा था, कभी-कभी सिर्फ सुविधा के लिए, कभी-कभी एक पर काबू पाने के लिए

अस्थायी संकट, कभी-कभी चिल्लाने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को खुश करने के लिए।

किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए जोर से और कम से कम एक बार। द.

नियमों में संशोधनों से अभ्यावेदनों की बाढ़ आ गई उच्च न्यायालय की सेवा के सदस्य और मानव प्रकृति

इसे आगे बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकार का समर्पण किसी व्यक्ति के हित या किसी वर्ग के हित। एक बार पता चला

कि राज्यपाल तैयार करते समय उच्च न्यायालय की उपेक्षा या अवज्ञा कर सकता है

सेवा के नियम, सत्ता का केंद्र न्यायालय से स्थानांतरित हो गया

मंत्रालय जो एक अवांछनीय स्थिति है क्योंकि इस प्रकार

न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है।

पुष्टि, वरिष्ठता और न्यायसंगत योग्यता के बारे में प्रश्न

प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के वितरण ने उच्च न्यायालय को परेशान किया था

लगभग दो दशकों तक, अलग हरियाणा राज्य बनने से पहले भी का गठन किया गया। ये प्रश्न और भी जटिल हो गए थे

संबंधित राज्य द्वारा 1963 के नियमों में किए गए परिवर्तन

पंजाब और हरियाणा की सरकारें। श्री एन. एस. राव का मामला,

जो हरियाणा रिट याचिका का प्रतिवादी 3 है, एक वाक्पटु है

नियमों में किए गए संशोधनों के प्रभाव का चित्रण

पूर्वव्यापी प्रभाव। उस समय जब हरियाणा के राज्यपाल 1 अप्रैल, 1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 1972 में नियमों में संशोधन किया गया।

श्री एन. एस. राव हरियाणा सुपीरियर में एकमात्र सीधी भर्ती थे।

न्यायिक सेवा। उन्हें 7 जुलाई, 1970 को परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था।

संशोधन को 1 अप्रैल, 1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।

मानो उसे और उसे अकेले पदच्युत करने के लिए।

जहाँ तक हरियाणा रिट याचिकाओं का संबंध है, कुछ समय के लिए

कुछ पदोन्नतियों की पुष्टि का प्रश्न, जिसमें शामिल हैं याचिकाकर्ता, स्थायी पदों के खिलाफ जो कोटा [1981] 1 एस. सी. आर. के अंतर्गत आते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4 2

छह स्थायी पदों में से पदोन्नत जो नए बनाए गए थे एड डब्ल्यू. ई. एफ. 18 जनवरी, 1972। इससे पहले कि उच्च न्यायालय निर्णय ले सके

उपरोक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नति की पुष्टि का प्रश्न,

प्रत्यर्थी 3 ने फरवरी को उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन दिया

13 , 1972 तर्क देते हुए कि 2 का अनुपातः 1 पदोन्नतियों के बीच

और प्रत्यक्ष भर्तियों को सभी चरणों में बनाए रखा जाना था, अर्थात,

न केवल नियुक्ति के समय बल्कि पुष्टि के समय भी

भी। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने पुष्टि को स्थगित कर दिया है

प्रत्यर्थी 3 के प्रतिनिधित्व के जवाब में पदोन्नति। बाद में

प्रतिवादी 3 की पुष्टि 7 जुलाई, 1972 से हुई थी। पाँच

तीन याचिकाकर्ताओं सहित पदोन्नति की पुष्टि डब्ल्यू. ई. एफ. जुलाई में की गई थी।

` 8 , 1972 , अर्थात्, उत्तरदाता 3 की पुष्टि होने के एक दिन बाद। गवर्नर

न ही हरियाणा ने पुष्टि के आदेश को मान्यता देने से इनकार कर दिया

प्रत्यर्थी 3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया और उसने बाद वाले को वापस कर दिया

23 जून, 1973 को डब्ल्यू. ई. एफ. जिला अटॉर्नी का पद। उत्तरदाता 3

रिट याचिका संख्या 2147 द्वारा उनके प्रत्यावर्तन के आदेश को चुनौती दी गई

1973. याचिका की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ द्वारा की गई थी

उच्च न्यायालय जिसने प्रत्यर्थी के प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द कर दिया 3

लेकिन बहुमत द्वारा अभिनिर्धारित कि प्रत्यर्थी 3 की पुष्टि का आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया अमान्य था क्योंकि पुष्टि करने की शक्ति

जिला और सत्र न्यायाधीश राज्यपाल में निहित थे न कि

उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के निर्णय में सूचित किया जाता है

नरेंद्र सिंह राव बनाम। हरियाणा राज्य (1)। ऊँचे का दृश्य पुष्टि की शक्ति के संबंध में न्यायालय को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया गया था

उच्च न्यायालय में 24 जनवरी, 1975 के अपने निर्णय द्वारा

पंजाब और हरियाणा बनाम। हरियाणा राज्य। (2) . यह आयोजित किया गया था

यह न्यायालय कि जिला और सत्र न्यायाधीश की पुष्टि करने की शक्ति

वे उच्च न्यायालय में रहते हैं, राज्यपाल में नहीं।

याचिकाकर्ता संख्या 1 ने तब उच्च न्यायालय में अभ्यावेदन किया

12 फरवरी और 31 मार्च, 1975 को उस भर्ती का विरोध करते हुए

उच्च न्यायिक सेवा केवल कोटा के नियम द्वारा शासित थी और रोटेशन के नियम से भी नहीं; इसलिए, यह इसके लिए खुला नहीं था

उच्च न्यायालय प्रोमो की पुष्टि के लिए मनमाने ढंग से तारीख देगा

टीज़। याचिकाकर्ता 2 और 3 ने भी इसी तरह के अभ्यावेदन दिए। में

इस बीच हरियाणा के राज्यपाल ने हर द्वारा नियम 12 में संशोधन किया।

याना प्रथम संशोधन नियम 1972 का प्रावधान है कि वरिष्ठता

सेवा के सदस्य, प्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नत अधिकारी, किसी पद पर निरंतर सेवा की अवधि से निर्धारित किया जाए

सेवा चाहे जो भी हो या पुष्टि की तारीख। के अनुसरण में

उस संशोधन पर, उच्च न्यायालय ने एक प्रशासनिक आदेश द्वारा निर्णय लिया

दिनांक 2 नवंबर, 1975 कि याचिकाकर्ता उनसे वरिष्ठ थे

(1) आई. एल. आर. [1974] 1 पुंज। & हर. 121 .

(2) [1975] 3 एस. सी. आर. 365, बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़ सी. जे.)

10

उत्तरदाता 3. हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इसने याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया है कि पुष्टि के समय आवर्तन का नियम लागू नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित है कि याचिकाकर्ता

संशोधित नियम 12 के कारण प्रत्यर्थी 3 से वरिष्ठ थे, बाद वाले ने संशोधित नियम 12 के अधिकारों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में 1977 की संख्या 100 पर एक और रिट याचिका दायर की। उस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, हरियाणा के राज्यपाल ने अप्रैल 1972 में नियमों में किए गए संशोधन को रद्द करते हुए 2 सितंबर, 1977 की अधिसूचना द्वारा नियमों में फिर से संशोधन किया। इस प्रकार मूल नियम 12 को बहाल करने के बाद, उच्च न्यायालय ने 3 की रिट याचिका पर इस आधार पर विचार किया कि वह स्वतः ही याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ हो गया था। इसलिए उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को प्रतिवादी 3 और श्री जे. एम. टंडन (अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) के बीच अंतर वरिष्ठता के सवाल तक सीमित कर दिया। द.

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है क्योंकि 6 जून, 1978 को प्रतिवादी 3 को अनुमति दी गई थी

चयन श्रेणी, संभवतः इस आधार पर कि वह याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ थे। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने ये रिट याचिकाएं दायर कीं।

अनुच्छेद के तहत (1978 का 4228 से 4230)। 32 संविधान का, निम्नलिखित राहतों का दावा करना:

(क) उत्तरदाता 1 और 2 (राज्य) को निर्देश देते हुए प्रमाणपत्र का एक रिट

हरियाणा और पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय

क्रमशः) 4 मई, 1973 के आदेश को रद्द करने के लिए जहां प्रत्यर्थी द्वारा 3 की पुष्टि डब्ल्यू. ई. एफ. 7 जुलाई, 1972 से की गई थी और

चयन श्रेणी प्रदान करने के लिए 6 जून, 1978 का आदेश

उसे;

(ख) नियमों के नियम 12 को उल्लंघन घोषित करने वाला आदेश पत्र।

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की गारंटी

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत; और

(ग) उत्तरदाता 1 और 2 को प्रतिबंधित करने वाली निषेध की एक रिट

नई वरिष्ठता सूची पर या उसके अनुसरण में कोई कार्रवाई करना

4 मई, 1973 और 6 जून, 1978 के आदेश।

यह पदोन्नति और पदोन्नति के बीच विवाद की उत्पत्ति है।

हरियाणा में सीधी भर्तियाँ। पंजाब में हालात बेहतर नहीं थे।

आकार, हालांकि यह इसके राज्यपाल के श्रेय के लिए कहा जाना चाहिए कि नहीं संशोधन किसी भी व्यक्तिगत न्यायिक पर बुरी नजर से किया गया था

अधिकारी। 1975 में, पदोन्नत अधिकारियों के संघ ने एक पुनः गठन किया

राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इससे बचने के लिए

पदोन्नतियों को पुष्टि की मनमाने तारीखें दी जा रही हैं, जारी रखें

सेवा में हमारा कार्यपालन और पुष्टि की तारीख नहीं होनी चाहिए

वरिष्ठता के मानदंड के रूप में स्वीकार किया जाए, जैसा कि [1981] 1 एस. सी. आर. के मामले में किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14

पंजाब सरकार के अन्य कर्मचारी। राज्य सरकार

उस अभ्यावेदन को अपनी टिप्पणियों के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया गया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने मामले को अपने पास लंबित रखा है।

कुछ समय के लिए। 1976 में किसी समय राज्य सरकार ने अल्टीमेटम दिया था।

धीरे-धीरे उच्च न्यायालय को एक मसौदा अधिसूचना का प्रस्ताव भेजा

नियमों में संशोधन। ऐसा लगता है कि सरकार ने तब ऐसा नहीं किया था

प्रस्तावित संशोधन। उस समय तक कोटे में दस रिक्तियां थीं। पदोन्नत अधिकारी उपलब्ध हो गए थे और समान संख्या में

पदोन्नत अधिकारी तीन साल से अधिक समय से अड्डी के रूप में कार्य कर रहे थे।

राष्ट्रीय जिला और सत्र न्यायाधीश। हालांकि, उच्च न्यायालय ने

उन रिक्तियों में पदोन्नति की पुष्टि न करें। इसके विपरीत, आशंका है कि नियम 12 में प्रस्तावित संशोधन दिया जा सकता है

पूर्वव्यापी प्रभाव से, उच्च न्यायालय ने पदोन्नति की पुष्टि की और

रोटेशन के नियम को लागू करके सीधी भर्ती। इसने एक अधिसूचना जारी की

यह 25 अगस्त, 1976 को पंजाब में प्रकाशित हुआ था।

3 सितंबर, 1976 का सरकारी राजपत्र, जिसमें उत्तर दिया गया है 3 से 8 की तुलना में पुष्टि की पूर्व तिथियाँ दी गई थीं

पदोन्नति देते हैं। आठ पदोन्नति की पुष्टि स्पष्ट रूप से हुई थी

स्थगित कर दिया। उत्तरदाताओं 6 से 8 के मामले में, प्रोबा की अवधि

उच्च न्यायालय द्वारा दो वर्ष की अवधि को काफी कम कर दिया गया था।

प्रतिवादी 6, श्री बी. एस. नेहरा को अप्रैल में परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। 1 , 1975 और 2 अगस्त, 1976 को इसकी पुष्टि की गई। उत्तरदाता 7, श्री

टी. एस. चीमा को 2 अप्रैल, 1975 को परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था और

5 अगस्त, 1976 को पुष्टि की गई। प्रत्यर्थी 8 श्री जे. एस. सिद्धू थे

11 अप्रैल, 1975 को नियुक्त किया गया और से प्रभाव के साथ पुष्टि की गई

8 अगस्त, 1976। इस प्रकार, इन प्रत्यक्ष भर्तियों की पुष्टि की गई

उनकी नियुक्ति के बाद एक वर्ष और चार महीने की अवधि, हालांकि

परिवीक्षा की सामान्य अवधि दो वर्ष है।

25 अगस्त, 1976 की अधिसूचना जारी होने पर,

याचिकाकर्ता 1 ने उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन को संबोधित करते हुए कहा कि

वह उच्च न्यायिक सेवा में कार्य कर रहा था

12 नवंबर, 1969 और यह कहते हुए कि उनकी पुष्टि की जानी चाहिए पद जो 23 दिसंबर, 1972 से उपलब्ध हुआ। वह शिकायत करता है।

पुष्टि की तारीख के विरुद्ध, 3 फरवरी, 1975, के लिए आवंटित

उसे मनमाने तरीके से।

इसके बाद राज्यपाल ने नियमों के नियम 12 में संशोधन किया।

पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर, 1976 की अधिसूचना द्वारा

9 अप्रैल, 1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया। उस संशोधन द्वारा,

वरिष्ठता का निर्धारण निरंतर सेवा की अवधि से किया जाना था।

सेवा में किसी पद पर, पुष्टि की तारीख चाहे जो भी हो। प्रत्यक्ष भर्तियाँ, उत्तरदाता 4 से 9, ने एक अभ्यावेदन को संबोधित किया

उच्च न्यायालय ने यह तर्क देते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उनकी वरिष्ठता

बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

न्यायालय की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 1976, के संदर्भ में

उनकी पुष्टि की संबंधित तिथियों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने नियम 12 की वैधता को भी चुनौती दी।

प्रो के उन परस्पर विरोधी दावों पर विचार करने के उद्देश्य से

न्यायाधीशों और प्रत्यक्ष भर्तियों, उच्च न्यायालय ने एक उप-आयोग का गठन किया तीन न्यायाधीशों वाली समिति, एस. एस. संधवालिया (अब मुख्य न्यायाधीश)

न्यायमूर्ति), भोपिंडर सिंह ढिल्लों और जे. जे. वर्णम सिंह। द कॉम समिति ने 7 फरवरी, 1979 को प्रतिनिधि को मौखिक सुनवाई दी।

पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों की संख्या। उच्च न्यायालय, कैसे

कभी, पदोन्नति और प्रत्यक्ष की वरिष्ठता को फिर से समायोजित नहीं किया है

संशोधित नियम 12 के आलोक में भर्ती।

दिलचस्प बात यह है कि उप-समिति की सुनवाई से पहले

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों ने अपनी बात रखी। 13 दिसंबर, 1977 को 1977 के सिविल रिट 100 में निर्णय जो

श्री एन. एस. राव द्वारा दायर किया गया था, जो हरियाणा में प्रतिवादी 3 हैं। याचिका। उपरोक्त निर्णय द्वारा जो ए. आई. आर. 1978 में सूचित किया गया है।

(पी और एच) 234, उच्च न्यायालय ने श्री राव की याचिका को खारिज कर दिया कि

नियमों में न केवल कोटा के नियम को लागू करने की आवश्यकता थी

नियुक्ति का समय लेकिन उन्हें एक नियम लागू करने की भी आवश्यकता थी

और 12 एक दूसरे से स्वतंत्र थे, कि घूर्णन प्रणाली कर सकते हैं नियम 8 द्वारा प्रदान किए गए कोटा नियम में निहित रूप से नहीं पढ़ा जाएगा और

कि उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य दावा करने के हकदार थे

नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से वरिष्ठता। पदोन्नति पाने वालों की शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक कार्यों के प्रयोग में दिए गए इस निर्णय का उच्च न्यायालय द्वारा

अपने प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन में पालन नहीं किया जा रहा है। 31 दिसंबर, 1976 की अधिसूचना द्वारा नियम 12 के संशोधन के बाद, जिला और सत्र न्यायाधीशों की दो रिक्तियां उत्पन्न हुईं और इनमें से प्रत्येक अवसर पर उच्च न्यायालय ने उनकी पुष्टि की तारीख को वरिष्ठता का मानदंड मानते हुए एक सीधी भर्ती को बढ़ावा दिया। न्यायिक विभाग के अधिकारियों की त्रैमासिक श्रेणीकरण और वितरण सूची, जिसे उच्च न्यायालय प्रकाशित करता है, में अंतर वरिष्ठता को पुष्टि की तारीखों के अनुसार दिखाया गया है, न कि संशोधित नियम 12 के अनुसार। पदोन्नत लोगों की शिकायतों में से एक यह है कि उच्च न्यायालय ने हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नियम 12 में किए गए संशोधनों के अनुपालन में त्रैमासिक श्रेणीकरण सूची में संशोधन किया, लेकिन संशोधित नियम 12 के अनुपालन में पंजाब अधिकारियों की श्रेणीकरण सूची में संशोधन नहीं किया।

हेंम -

हिन।

}

[1981] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है

सुरक्षा, संतुष्टि और कल्याण की भावना। ऐसा कहा जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा 25 अगस्त, 1976 को अधिसूचना जारी करने के बाद पदोन्नति के कोटे के भीतर आठ और रिक्तियां पैदा हुईं, लेकिन प्रो

मोती, जो तीन साल से अधिक की अवधि के लिए कार्य कर रहे थे,

उन पदों पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

याचिकाकर्ताओं की अन्य शिकायतों में से एक यह है कि

न्यायालय ने पंजाब के राज्यपाल द्वारा किए गए संशोधन पर कार्रवाई की 31 दिसंबर, 1976 को 'नियुक्ति द्वारा संवर्ग पद' की परिभाषा में

उच्च न्यायिक सेवा में अस्थायी पदों पर सीधी भर्ती।

हालाँकि इसने उसी अधिसूचना द्वारा किए गए अन्य संशोधन को नजरअंदाज कर दिया

नियम 12 में संशोधन, जिसके तहत निरंतर

कार्यनिष्ठा वरिष्ठता की परीक्षा है।

उच्च द्वारा तैयार की गई श्रेणीकरण सूची से व्यथित होना

पंजाब में अदालत, पदोन्नतों ने 1979 की रिट याचिका 266 दायर की है। इस न्यायालय में निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया है:

((i) विवादित को निरस्त करने वाला एक उपयुक्त रिट या निर्देश।

अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त, 1976;

((ii) उच्च न्यायालय को आरोपमुक्त करने का निर्देश देने वाला आदेश पत्र।

वरिष्ठता को फिर से निर्धारित करने का संवैधानिक दायित्व

पंजाब सुपीरियर जुडिशल के सभी सदस्यों के बीच

नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार सेवा,

31 दिसंबर, 1976 की अधिसूचना द्वारा संशोधित और

श्रेणीकरण और वितरण सूचियों में सुधार करना,

तदनुसार;

((ग) राज्य सरकार को निर्देश देते हुए एक उपयुक्त रिट और

उच्च न्यायालय याचिकाकर्ताओं की पुष्टि करने के लिए

जिन तिथियों में रिक्तियां उत्पन्न हुईं और उपलब्ध हुईं रोटेशन के नियम को लागू किए बिना उनका कोटा;

((iv) उच्च न्यायालय को विचार करने का निर्देश देने वाली एक उपयुक्त रिट।

नए सिरे से जिले की चार रिक्तियों को भरने का मामला और

सत्र न्यायाधीश जो 9-4-1976 के बाद हुए और

वरिष्ठता और पुष्टि की संबंधित तिथियों को फिर से समायोजित करें

याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं के 3 से 11 के अनुसार संशोधित नियम 12 के साथ;

(v) पंजाब राज्य को प्रतिबंधित करने वाला निषेध का एक रिट और

उच्च न्यायालय ने पूर्व में निर्धारित वरिष्ठता पर कार्य करने से

नियम 12 का संशोधन, किसी भी उद्देश्य के लिए,

सेवा के भीतर और पदोन्नति सहित; और

(vi) नियमों के नियम 11 को रद्द करते हुए प्रमाण पत्र का एक रिट

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटी।

बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

ये तब संबंधित शिकायतें और मांगें हैं

के सुपीरियर न्यायिक सेवाओं में रोमोटी और प्रत्यक्ष भर्ती

पंजाब और हरियाणा। जहाँ तक उच्च न्यायालय का संबंध है, उसके

दृष्टिकोण को दिनांकित [ए. 2,1978 की रिपोर्ट की भाषा में सबसे अच्छा कहा जा सकता है जो उप-समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

इसके तीन विद्वान न्यायाधीश हैं। पृष्ठभूमि निर्धारित करने के बाद

विवाद पर, रिपोर्ट में कहा गया है:

" यह उपरोक्त संदर्भ में है कि प्रश्न स्पष्ट रूप से

और स्पष्ट रूप से उत्पन्न होता है, क्या वरिष्ठता का निर्धारण

सेवा के सदस्य एक ऐसा मामला है जो अनन्य के भीतर है

के एक आवश्यक परिणाम के रूप में उच्च न्यायालय की अधिकारिता

संविधान के अनुच्छेद 235 के आधार पर इसमें निहित नियंत्रण

भारत से। यदि ऐसा है, तो यह स्पष्ट है कि किसी भी घुसपैठ में उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस नियंत्रण का क्षेत्र

यह अनुचित होगा और इसलिए असंवैधानिक होगा। हम हैं।

इस बात का दृढ़ दृष्टिकोण कि सिद्धांत और तर्क दोनों के आधार पर वर्तमान अधिकारियों की प्रवृत्ति, यह स्पष्ट प्रतीत होती है

कि न्यायिक सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता इतनी है कि

उन पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण के लिए अभिन्न और महत्वपूर्ण,

कि इसका कोई भी क्षरण दोनों अनुच्छेद 235 का उल्लंघन होगा

संविधान का और समान रूप से तय किए गए संघ के विपरीत चलता है

न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो अब बन रही है

संविधान की मूल विशेषता के रूप में मान्यता प्राप्त।

यह

यह एक फोर्टिओरी का अनुसरण करता है कि यदि वरिष्ठ के सदस्यों की वरिष्ठता

न्यायिक सेवा को एक बार नियंत्रण में नहीं माना जाता है

अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय, तो, वास्तव में, यह हो सकता है बिना नियमों के राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित

यहां तक कि उच्च न्यायालय के साथ संदर्भ या परामर्श भी। इस तरह की

स्थिति पूरी तरह से विसंगत और पूरी तरह से विनाशकारी होगी

जिला अदालतों और अदालतों पर अनन्य नियंत्रण

अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय में निहित इसके लिए अध्यादेश। 235. यह ए. पी

नाशपाती को सिद्धांत और पूर्ववर्ती दोनों के आधार पर अच्छी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए

सदस्यों की वरिष्ठता निर्धारित करने की शक्ति

सेवा संभवतः इसके अलावा किसी अन्य प्राधिकरण में निहित नहीं की जा सकती है

उच्च न्यायालय। उदाहरण के लिए, यह मौजूदा प्रावधानों पर लागू नहीं हो सकता है।

राज्यपाल या राज्य सरकार में निहित किया जाए। इसलिए, हमें ऐसा लगता है कि राज्य सरकार क्या नहीं कर सकती

प्रत्यक्ष रूप से, इसे नियम बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

यहां तक कि पुण्य से उसमें निहित कार्यकारी शक्ति के प्रयोग से भी

अनुच्छेद 309 और परामर्श या सूचित किए बिना भी

उच्च न्यायालय। हालाँकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कला। 309 विषय है

संविधान के अन्य प्रावधानों के लिए। इसलिए,

उच्च न्यायालय [1981] 1 एस. सी. आर. में निहित अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 235 द्वारा अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 309 को कहीं भी ओवरराइड करना चाहिए।

दोनों में टकराव होता है। नतीजतन, यदि वरिष्ठता है

विशेष रूप से उच्च न्यायालय के नियंत्रण के दायरे में,

तब इसे गुप्त रूप से दोनों में से किसी पर भी सीधे घुसपैठ नहीं किया जा सकता है।

या बिना अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने के कुटिल तरीके से यहां तक कि उच्च न्यायालय के साथ संदर्भ या परामर्श भी।

" एन. एस. राव के मामले के अनुपात में अंतर्निहित वास्तविक तर्क

और उनके सर्वोच्च प्रभुओं के बाद के निर्णय

जिस न्यायालय के लिए एक संदर्भ का पालन किया जाएगा, वह प्रतीत होता है कि जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का क्षेत्र

अनुच्छेद 235 के तहत इसमें कोई द्वैत नहीं हो सकता है। वहाँ एक ओर उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रण मौजूद नहीं हो सकता है और

राज्य सरकार या दूसरी ओर राज्यपाल। इसलिए,

स्थिति यह है कि वरिष्ठता राज्य द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए

न्यायालय को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे मन में यह नियंत्रण की द्वैतता का एक पेटेंट उदाहरण होगा जिसके खिलाफ

अंतिम न्यायालय ने दृढ़ता से अपना चेहरा तय कर लिया है।

" सिद्धांत रूप में, इसलिए हमारा विचार है कि वरिष्ठ

उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों का अधिकार विशेष रूप से है

अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय के नियंत्रण में और

इसलिए, राज्य सरकार गठन करने के लिए सक्षम नहीं है या

इसके संबंध में नियमों में परिवर्तन करें।

इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों की जांच करते हुए, रिपोर्ट इस प्रकार निष्कर्ष निकालती है:

" सिद्धांत और पूर्ववर्ती दोनों के आधार पर हमारा मानना है कि

उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता

पूरी तरह से उच्च न्यायालय के नियंत्रण में निहित नहीं हो सकता है

नियमों के निर्माण और पुनर्निर्धारण द्वारा घुसपैठ की गई

राज्य सरकार, जिसे वह बनाने और लागू करने के लिए सक्षम नहीं है

नियम 12 संविधान के अनुच्छेद 235 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

" एक बार जब हम उस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं, तो यह स्पष्ट है कि जब तक

न्यायिक पक्ष, अविभाज्य निर्धारित करने के लिए कोई ठोस आधार मौजूद नहीं हो सकता है सेवा के सदस्यों की दोहरी वरिष्ठता-दोनों

प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति-जिनके असंख्य प्रतिनिधि हैं

ये समितियों के समक्ष हैं। इससे पहले उच्च न्यायालय ने

पहले के कुछ संशोधनों के आधार पर कार्रवाई की गई

नियम और प्रशासनिक पक्ष पर यह स्पष्ट रूप से होगा

अब एक विरोधाभासी स्थिति लेने में अक्षम। अन्यथा भी।

वर्तमान मामले में हमें बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.) पर कार्रवाई करना उचित नहीं लगता है।

1

प्रशासनिक रूप से कथित उद्घोषणा का उल्लंघन करते हुए

बिन्दु पर नियम। इस प्रकार वैधानिक के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

एक बाध्यकारी और आधिकारिक निर्णय के लिए मामले को स्पष्ट रूप से रखें

न्यायिक पक्ष को तुरंत सूचित करें "।

" उच्च न्यायालय अनिवार्य रूप से स्वतंत्र लोगों का संरक्षक है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा की गरिमा और अखंडता, जिसकी

नियंत्रण संवैधानिक रूप से इसमें निहित है। एक संस्था के रूप में, यह मूल रूप से इन लक्षणों के रखरखाव में रुचि रखते हैं। हम.

यह विचार है कि एक निजी को धक्का देना अभेद्य होगा

वादी या न्यायिक सेवा के प्रभावित सदस्यों में से कोई एक

आवश्यक निर्णय लेने के लिए कानून की अदालत के खिलाफ।

यह

इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा भी बोझ उठाया जाना चाहिए। हम. फलस्वरूप यह सिफारिश की जाएगी कि पंजीयक को निर्देश दिया जाए कि

के अनुच्छेद 226 के तहत तुरंत आवश्यक कार्यवाही शुरू करें

उच्च न्यायालय की ओर से भारत का संविधान।

" एक बार जब यह तय हो जाता है कि वरिष्ठता का निर्धारण

उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य विशेष रूप से निहित हैं

उच्च न्यायालय, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह का नियंत्रण अनिवार्य रूप से exer बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति का तात्पर्य है

इस तरह के नियंत्रण को संभव, सुविधाजनक और प्रभावी बनाना। यह है

हाल ही में संविधान पीठ के फैसले की रिपोर्ट में तय किया गया था

यू. पी. राज्य बनाम त्रिपाठी, ए. आई. आर. 1978 (खण्ड। 2) एस. सी. मामले

पृष्ठ 102। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि इसके लिए नियम

सदस्यों के बीच वरिष्ठता का निर्धारण

उच्च न्यायिक सेवा को संतुष्ट करने के लिए तैयार किया जा सकता है

पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती दोनों की शाखाएँ "। प्रो द्वारा इस अदालत में हरियाणा रिट याचिका दायर की गई थी।

जुलाई 1978 में याचिका दायर की गई और फरवरी 1979 में पंजाब रिट याचिका दायर की गई। इस प्रकार उच्च न्यायालय को अपने समक्ष अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करने की आवश्यकता और उस पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक होने की शर्मिंदगी से बख्शा गया।

विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने पेश किए गए तर्क

पदोन्नत, सीधी भर्ती, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं लेकिन उन तर्कों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, वकील द्वारा उठाए गए प्रश्न खुद को दो मुद्दों में हल करते हैं। वे हैं (1) जिला और सत्र न्यायाधीशों की वरिष्ठता के नियम बनाने की शक्ति राज्यपाल में निहित है या उच्च न्यायालय में। और (2) क्या उच्च न्यायालय, स्वयं को कोटा के नियम पर आधारित करते हुए, जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्ती के समय आवर्तन के नियम को लागू करने में उचित है।

[198

1] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

0

पहले प्रश्न का निर्णय दायरे, माध्य पर निर्भर करता है।

अनुच्छेद 309 और आरती में निहित प्रावधानों का निर्धारण और उनका उद्देश्य

संविधान का अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 309 इस प्रकार कहता है:

" 309. इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम

उपयुक्त विधानमंडल भर्ती को विनियमित कर सकता है, और

लोक सेवाक लेल नियुक्त व्यक्तिक सेवाक शर्तसभ

और संघ या एन. वी. के मामलों के संबंध में पद

बताइए:

बशर्ते कि यह राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति के लिए सक्षम होगा।

सेवाएँ और पदों के मामले में वह व्यक्ति जिसे वह निर्देश दे सकता है संघ के मामलों के साथ संबंध, और राज्यपाल के लिए

किसी राज्य या ऐसे व्यक्ति का जिसे वह सेवाओं के मामले में निर्देश दे।

और राज्य के मामलों के संबंध में पद, बनाने के लिए

भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम

उस ओर से उपयुक्त के एक अधिनियम द्वारा या उसके तहत किया जाता है इस अनुच्छेद के अधीन विधानमंडल और इस प्रकार बनाए गए किसी भी नियम के

ऐसे किसी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए।

अनुच्छेद 235 इस प्रकार कहता है:

" 235. जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

पदस्थापन और पदोन्नति सहित, और

न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों को छुट्टी का अनुदान

राज्य और जिला न्यायाधीश के पद से कम का कोई भी पद धारण करना

उच्च न्यायालय में निहित किया जाएगा, लेकिन इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं

ऐसा समझा जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से कुछ भी छीन ले रहा है।

अपील का अधिकार जो उसे विनियमित करने वाले कानून के तहत हो सकता है

उसकी सेवा की शर्तें या उच्च न्यायालय को सौदा करने के लिए अधिकृत करने के रूप में

शर्तों के अनुसार उसके साथ अन्यथा ऐसी कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा।

इसका आग्रह श्री वी. एम. तारकुंडे द्वारा किया जाता है जो उनकी ओर से पेश होते हैं।

हरियाणा में प्रचार करता है कि यदि अनुच्छेद 235 के दो भाग हैं

एक साथ पढ़ें, यह स्पष्ट होगा कि नियंत्रण जो उच्च न्यायालय

जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रयोग करने का हकदार है

इसमें विनियमन करने वाले नियम बनाने की शक्ति शामिल नहीं है

परामर्श, वह शक्ति जिसे संविधान ने प्रदान किया है अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा राज्यपाल एक विधायी है न कि एक

कार्यकारी शक्ति; और चूंकि राज्यपाल एक विधायी शक्ति का प्रयोग करता है अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत नियम बनाते समय,

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वहां किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया है

द्वारा। वकील का कहना है कि न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है

कार्यकारी हस्तक्षेप, न कि कानूनों से स्वतंत्रता।

बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

श्री ए. के. सेन, श्री एस. एन. कक्कड़, डॉ. वाई. एस. चिताले, श्री एफ. एस. नरीमन और श्री बी. आर. तुली ने श्री तार के तर्क का समर्थन किया।

इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए

न्यायालय, संविधान के संबंधित प्रावधान और संविधान सभा की बहस। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल, श्री सोराबजी द्वारा यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 235 का सर्वोपरि उद्देश्य न्यायपालिका को निष्पादन संबंधी हस्तक्षेप से बचाकर उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है, जो यह मानता है कि एक बार न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति हो जाने के बाद, उसका बाद का कार्यकाल उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होना चाहिए। उसे अपने न्यायिक जीवन के दौरान किसी भी अनुचित कार्यकारी दबाव की संभावना से अवगत नहीं कराया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण, जो अनुच्छेद 235 द्वारा उच्च न्यायालय में निहित है, प्रकृति में अनन्य है, विस्तार में व्यापक और संचालन में प्रभावी है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि इन मामलों में कोई द्वंद्व नहीं हो सकता है, और इसलिए न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति उच्च न्यायालय में होनी चाहिए न कि राज्यपाल में। सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, यह अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का एक आवश्यक परिणाम है जो उच्च न्यायालय में निहित है।

इस सवाल पर कोई सीधा निर्णय नहीं है कि क्या सरकार

न ही, अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में,

राज्य के न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति रखता है। इस पर मिसाल न होने का कारण जब कानूनी रिपोर्ट संवैधानिक निर्णयों से भरी हुई होती हैं,

शायद यह है कि हमारे काम करने के पिछले तीस वर्षों के दौरान

संविधान, किसी ने कभी राज्यपाल की शक्ति पर विवाद नहीं किया न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले नियम बनाएँ। कई राज्यों में राज्य द्वारा पारित कानून के अभाव में ऐसे नियम लागू हैं।

इस विषय पर विधायिका और उच्च न्यायालय इन्हें लागू करते रहे हैं

समय-समय पर नियम और बिना किसी आपत्ति के मामले-दर-मामले। यह भी है

यह महत्वपूर्ण है कि शायद ही किसी उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के नियम बनाए हों

अपने न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए। यहाँ तक कि ऊँचे

पंजाब और हरियाणा की अदालत, जो सरकार के अधिकार और न ही नियम बनाने के अधिकार पर विवाद करती है, ने कब्जा करने के लिए अपना कोई नियम नहीं बनाया है।

उस क्षेत्र में। यह सब, जो एक कठोर इतिहास है, को खारिज नहीं किया जा सकता है

यह कहते हुए कि एक मिसाल की अनुपस्थिति यह मानने के लिए कोई अधिकार नहीं है कि जिसे चुनौती नहीं दी गई है वह विधिसम्मत है। यह सच है कि नवीनता

एक विवाद इसकी दुर्बलता नहीं हो सकती है और वास्तव में कानून ने

यदि इसे [1981] 1 एस. सी. आर. से बढ़ने नहीं दिया गया होता तो स्थिर और स्थिर रहता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2

केस टू केस। लेकिन बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ है।

उच्च न्यायालयों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा नियमों में असंबद्ध स्वीकृति

राज्यपालों द्वारा तैयार किया गया। हरियाणा में ही, प्रतिवादी 3, श्री एन. एस. राव ने अपने आदेश को ओवरराइड करने की राज्यपाल की शक्ति को चुनौती दी

पुष्टि जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई थी। और वह जीत गया।

जब भी ऐसा करने के लिए एक औचित्य की झलक थी,

या तो एक या दूसरा पक्ष व्यक्तिगत हित से प्रेरित है या बाहर से

इस व्यापक विचार पर कि उच्च न्यायालय का नियंत्रित करने वाला न्यायशास्त्र

यह अनिवार्य रूप से अनुल्लंघनीय बना रहना चाहिए और इसके द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती दी है

राज्यपाल का अत्यधिक होना। लेकिन एक अच्छा कारण है कि

राज्यपाल द्वारा बनाए गए वरिष्ठता के नियमों को स्वीकार कर लिया गया है,

पूरे देश में, इन सभी वर्षों में। इसका कारण इस प्रकार है:

संविधान के अनुच्छेद 235 और 309 के एक सादे पठन पर,

यह स्पष्ट है कि अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति

राज्य की न्यायिक सेवा में राज्यपाल निहित है और नहीं

उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 235 का पहला भाग नियंत्रण निहित करता है।

जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय में उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर।

लेकिन उस लेख का दूसरा भाग कहता है कि लेख में कुछ भी नहीं है

किसी व्यक्ति से छीनने के रूप में समझा जाएगा राज्य की न्यायिक सेवा अपील का कोई भी अधिकार जो उसके पास हो सकता है

उसकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून के तहत या अधिकृत करने के रूप में

उच्च न्यायालय के अनुसार के अलावा उसके साथ व्यवहार करने के लिए

ऐसी विधि के अधीन विहित उसकी सेवा की शर्तें। अतः आरती अनुच्छेद 235 स्वयं उच्च न्यायालय की शक्ति की बाहरी सीमाओं को परिभाषित करता है

जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। में। सबसे पहले, जिला न्यायालयों पर अपने नियंत्रण के प्रयोग में

और अधीनस्थ न्यायालय, यह उच्च न्यायालय के लिए इनकार करने के लिए खुला नहीं है

राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा का एक सदस्य अधिकार

की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून द्वारा उसे दी गई अपील

उनकी सेवा। दूसरा, उच्च न्यायालय अपने आदेश का प्रयोग नहीं कर सकता है।

नियंत्रण की शक्ति, ऐसे व्यक्ति के साथ अन्यथा व्यवहार करें

उसकी सेवा की शर्तों के साथ जो ऐसी कानून द्वारा निर्धारित हैं।

इस तरह का कानून पारित करने की शक्ति किसके पास है? जाहिर है उच्च नहीं

न्यायालय क्योंकि, उच्च न्यायालय में कानून पारित करने की कोई शक्ति नहीं है,

यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग में बनाए गए नियम

उस ओर से उसे प्रदान किए जाने पर कानून की शक्ति हो सकती है। वहाँ है। कानून पारित करने की शक्ति और बनाने की शक्ति के बीच अंतर

नियम, जिनके पास कानून द्वारा कानून की शक्ति है। इसके अलावा, "कानून" जो

कला का दूसरा भाग। 235 बात करता है, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है

क्योंकि, यदि ऐसा नहीं था, तो यह कहने का कोई उद्देश्य नहीं था कि

उच्च न्यायालय की नियंत्रण की शक्ति को छीनने के रूप में नहीं माना जाएगा

उनकी स्थिति को विनियमित करने वाले कानून के तहत कुछ व्यक्तियों के कुछ अधिकार

सेवाएँ। संभवतः इसका बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.) होने का इरादा नहीं था।

बशर्ते कि उच्च न्यायालय की नियंत्रण की शक्ति के अधीन होगी

उसके द्वारा निर्धारित सेवा की शर्तें। स्पष्ट अर्थ है, वहाँ

इससे पहले, अनुच्छेद 235 के दूसरे भाग में नियंत्रण की शक्ति है

प्रथम भाग द्वारा उच्च न्यायालय में निहित होने से न्यायपालिका वंचित नहीं होगी।

अधिकारी या विधान द्वारा बनाए गए कानून द्वारा उसे प्रदत्त अधिकार उसे सेवा की शर्तों को विनियमित करना।

अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान नहीं करता है कि

संलग्न न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाएँ

जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों को। जब भी, इसका उद्देश्य किसी भी प्राधिकारी को ऐसा करने की शक्ति प्रदान करना था

की शर्तों से संबंधित नियमों सहित विशेष प्रावधान या नियम

संविधान ने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा है। देखें, के लिए उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 77 (3), 87 (2), 118,145 (1), 146 (1),

और 2 (148) (5), 166 (3), 176 (2), 187 (3), 208,225,227 (2) और (3),

229 (1) और (2), 234,237 और 283 (1) और (2)। इस फासिकुलस से बाहर

अनुच्छेद 225,227 (2) और (3) में निहित प्रावधान

और 229 (1) और (2) इस प्रश्न पर प्रासंगिक हैं, क्योंकि ये अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से

विशिष्ट उद्देश्य। अनुच्छेद 229 (2) जो सीधे बिंदु में है प्रदान करता है

द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन स्पष्ट शब्दों में

राज्य का विधानमंडल, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

उच्च न्यायालय के अधिकार ऐसे होंगे जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाएं।

मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा बनाए गए नियम

मुख्य न्यायाधीश द्वारा पुर के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत न्यायालय पोज देते हैं। उनके सामने इस विशेष प्रावधान के साथ, के निर्माता

संविधान इसी तरह के प्रावधान को शामिल करने में विफल नहीं होता

अनुच्छेद 235 में कहा गया है यदि यह अभिप्रेत था कि उच्च न्यायालयों को

जूडी की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से संबद्ध वरिष्ठ अधिकारी।

यह देखने के बाद कि संविधान प्रदान नहीं करता है

उच्च न्यायालय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति

जिला न्यायालयों और उप न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की सेवा

इसके लिए आदेश देते हुए, हमें इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि किसके पास है

वह शक्ति? अनुच्छेद 309 इसका उत्तर देता है। यह प्रावधान करता है कि अधिनियम

उपयुक्त विधायिका भर्ती और शर्तों को विनियमित कर सकती है।

संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएँ

संघ या किसी राज्य के कार्य। अनुच्छेद 248 (3) के साथ पढ़ा जाता है

सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 41, राज्य को प्रदान करती है

विधायिकाओं को "राज्य लोक सेवाओं" के संबंध में कानून पारित करने की शक्ति है जिसमें राज्य की न्यायिक सेवाएं शामिल होनी चाहिए। द "

अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की शक्ति। 235 इस प्रकार, उस अनुच्छेद की शर्तों द्वारा ही, कानून के अधीन किया जाता है

4

जिसे राज्य विधानमंडल भर्ती को विनियमित करने के लिए पारित कर सकता है [1981] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और राज्य के न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तें। की शक्ति

इस तरह के कानून को पारित करना स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा विचार नहीं किया गया था उच्च के "नियंत्रण क्षेत्राधिकार" पर अतिक्रमण के रूप में निर्माता

अनुच्छेद 235 के पहले भाग के तहत न्यायालय। उस पर नियंत्रण

जिला अदालतें और अधीनस्थ अदालतें उच्च न्यायालय में निहित हैं

न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने का आदेश। वह ऊँचा है

कार्यपालिका नहीं, बल्कि न्यायालय, जिसका राज्य न्यायपालिका पर नियंत्रण है

सीरी। लेकिन, जो बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है वह यह है कि संविधान जिसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक ध्यान रखा गया है

न्यायपालिका ने राज्य विधानमंडल की पारित करने की शक्ति को नहीं माना

न्यायपालिका की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली विधियाँ

उस स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में अधिकारी। केवल शक्ति

इस तरह का कानून पारित करना उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण का उल्लंघन नहीं है

राज्य न्यायपालिका पर न्यायालय।

यही इस संदर्भ में कला का परंतुक है। 309 प्रासंगिक मानता है

भाव और महत्व। राज्य विधानमंडल के पास पारित करने की शक्ति है

न्यायपालिका की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली विधियाँ

राज्य के अधिकारी। लेकिन एक उपयुक्त प्रावधान बनाना आवश्यक था।

कानून के पारित होने तक उस शक्ति के प्रयोग को सक्षम करना

उस विषय पर विधायिका द्वारा। संविधान इसके द्वारा प्रदान करता है

पर्याप्त सबूत प्रदान करता है कि यह एक निर्वात को नापसंद करता है। इसलिए यह

के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए

उस शक्ति का प्रयोग न करने वाली शक्ति का अंतिम भंडार। प्रावधान

कला के लिए। 309 जहां तक सामग्री का संबंध है, यह उपबंध करता है कि जब तक राज्य विधान

यदि किसी विशेष विषय पर कोई कानून पारित किया जाता है, तो वह सक्षम होगा -

राज्य का राज्यपाल भर्ती को विनियमित करने वाले नियम बनाएगा

और राज्य के न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तें। द.

इस प्रकार राज्यपाल तब हस्तक्षेप करते हैं जब विधायिका कार्य नहीं करती है। शक्ति।

इस प्रकार परंतुक के तहत राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक शक्ति है जो

विधायिका प्रयोग करने के लिए सक्षम है लेकिन वास्तव में अभी तक ऐसा नहीं किया है

सिसी। यह विधायिका की विशेषताओं में भाग लेता है, निष्पादन में नहीं। तीव, शक्ति। यह विधायी शक्ति है।

कि राज्यपाल के पास हमारे अधीन विधायी शक्ति है

संविधान निर्विवाद है और इसलिए, कुछ भी अद्वितीय नहीं है।

अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्यपाल की शक्ति के बारे में

विधायी शक्ति की प्रकृति में। अनुच्छेद 168 के अनुसार, राज्यपाल

राज्य का विधानमंडल राज्य के विधानमंडल का एक हिस्सा है: और सबसे ज्यादा

राज्यपाल द्वारा विधायी शक्ति का स्पष्ट प्रयोग शक्ति है

कला द्वारा उसे दिया गया। 213 अध्यादेशों को जारी करने के लिए जब कानून

ट्यूअर सत्र में नहीं है। उस अनुच्छेद के तहत, वह एक शक्ति का प्रयोग करता है

उसी प्रकार का जिसे विधायिका आम तौर पर शक्ति का प्रयोग करती है कानून बनाएँ। संविधान के भाग VI के अध्याय IV का शीर्षक

टियन, किस कला में। 213 होता है, महत्वपूर्ण है: "

बी. एस. यादव वी. हरियाणा की विधायी शक्ति (चंद्रचूड़, सी. जे.)

1

राज्यपाल "। अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत राज्यपाल की उचित नियम बनाने की शक्ति इसी तरह की है। यह विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 214 के तहत, वह विधान के स्थान पर ले जाता है क्योंकि विधानमंडल अवकाश में है। आरती क्ली 309 के प्रावधान के तहत, वह विधायिका के लिए प्रतिस्थापित करता है क्योंकि विधायिका ने अभी तक इस विषय पर एक उपयुक्त कानून पारित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है।

यह सच है कि अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति "के अधीन" है

संविधान के प्रावधान। लेकिन इस कारण से यह तर्क देना गलत है कि राज्यपाल न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम नहीं बना सकते हैं।

राज्य। सबसे पहले, अनुच्छेद 235 के पहले भाग द्वारा उच्च न्यायालयों को प्रदत्त नियंत्रण की शक्ति को स्पष्ट रूप से विषय बनाया गया है,

उस अनुच्छेद का दूसरा भाग, सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानूनों के लिए

इसके न्यायिक अधिकारियों के उप। अनुच्छेद 235 का पहला भाग, जैसा कि था, है -

एक परंतुक के अधीन जो क्षेत्र से एक अपवाद बनाता है

इससे ढका हुआ। दूसरा, राज्यपाल, समान रूप से व्यक्त शब्दों में, है अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा नियम बनाने की शक्ति दी गई

विषय। अनुच्छेद 235 और 309 के संयुक्त अध्ययन से यह पता चलेगा कि

परिणामस्वरूप कि यद्यपि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण निहित है उच्च न्यायालय, उपयुक्त विधानमंडल, और उस विधानमंडल तक

अधिनियम, राज्य के राज्यपाल के पास नियम बनाने की शक्ति है

विधान संविधान के अन्य सभी प्रावधानों के अधीन है जैसे, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 और 16। हमारे सामने यह सवाल उठाया गया है कि

मुख्य रूप से शक्ति के स्थान में से एक, इसकी सीमा का नहीं। द.

अनुच्छेद 235 का दूसरा भाग प्रदान करने की विधायी शक्ति को मान्यता देता है

न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए

राज्य से। अनुच्छेद 309 का मूल प्रावधान, जिसमें इसके

प्रावधान, बिजली के स्थान को ठीक करता है। आरती के प्रारंभिक शब्द

क्ली 309 उस शक्ति के आयाम को सीमित करता है।

हम इसमें कोई संदेह नहीं रखते कि वरिष्ठता सेवा की एक शर्त है।

और यह महत्वपूर्ण बात है। नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है

इसलिए अनुच्छेद 235 के पहले भाग द्वारा किसी भी कानून विनियमन के अधीन है।

उस अनुच्छेद के दूसरे भाग द्वारा परिकल्पित वरिष्ठता। द.

ऐसा कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 309 द्वारा विधायिका में निहित है।

और जब तक यह कार्य नहीं करता, राज्यपाल में। चाहे वह विधायिका हो जो

कोई अधिनियम पारित करता है या राज्यपाल जो वरिष्ठता को विनियमित करने वाले नियम बनाता है,

अंतिम उत्पाद के दूसरे भाग के अर्थ के भीतर 'कानून' है

अनुच्छेद 235। पंजाब और हरियाणा की विधानसभाएँ नहीं हैं

संबंधित राज्य न्यायिक की वरिष्ठता को विनियमित करने वाला एक अधिनियम पारित किया

दोनों राज्यों के अधिकारियों, राज्यपालों के पास व्यवस्था बनाने की शक्ति है

[1981] 1 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत उस उद्देश्य के लिए नियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी.

संविधान। इस तरह के नियम निश्चित रूप से इन प्रावधानों के अधीन हैं -

संविधान और किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के लिए जो

निजी विधायिका इस विषय पर पारित कर सकती है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, किसी कानून को पारित करने या पारित करने की केवल शक्ति

वरिष्ठता को विनियमित करने वाले कानून के बल वाले नियम नहीं बनाते हैं

जिले पर उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण पर प्रभाव डालना

अनुच्छेद 235 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय और न्यायालय। इस तरह का कानून

या नियम, जैसा भी मामला हो, सामान्य या अमूर्त के लिए प्रदान कर सकते हैं

वरिष्ठता के नियम, उन्हें प्रत्येक पर लागू करने के लिए इसे उच्च न्यायालय पर छोड़ देते हैं

व्यक्तिगत मामला जब और जब अवसर आता है। कानून की शक्ति

ज्येष्ठता के संविधान के अन्य सभी प्रावधानों के अधीन होने में देरी

इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो प्रभावित करेगा या हानिकारक होगा

अनुच्छेद 235 द्वारा उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण के लिए मानसिक। को।

एक आसान उदाहरण लें, राज्य विधानमंडल या राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं।

कानून द्वारा या वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले नियमों द्वारा प्रदान करें कि राज्य शासन

संबंधित विभाग में वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी

के नियमों के वास्तविक अनुप्रयोग द्वारा राज्य के न्यायिक अधिकारी

प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में वरिष्ठता। इस प्रकार, उच्च न्यायालय का कॉन

राज्य की न्यायपालिका पर नियंत्रण काफी हद तक बाधित हुआ होगा। अनुच्छेद 309 के प्रारंभिक शब्द, "इसके प्रावधानों के अधीन

अनुच्छेद 235। यह इस प्रकार है कि हालांकि विधायिका या राज्यपाल न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता को निर्धारित करके विनियमित करने की शक्ति है

सामान्य अनुप्रयोग के नियम, कि शक्ति का प्रयोग एक में नहीं किया जा सकता है

जिस तरह से निहित नियंत्रण में हस्तक्षेप होगा अनुच्छेद 235 के पहले भाग द्वारा उच्च न्यायालय। एक शब्द में, आवेदन

वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले कानून को उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। द.

प्रत्येक न्यायिक अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण एक

ऐसा मामला जो निर्विवाद रूप से उच्च के नियंत्रण के क्षेत्र में आता है

जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायालय। के लिए एक ही कारण, हालांकि भर्ती के नियम एक अवधि के लिए प्रदान कर सकते हैं

परिवीक्षा का, यह सवाल कि क्या किसी विशेष न्यायिक अधिकारी के पास है

संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा पूरी की या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जो

विशेष रूप से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। यह समझाता है

आंशिक रूप से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम। हरियाणा राज्य (1)

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक अधिकारी की पुष्टि करने की शक्ति निहित है

उच्च न्यायालय में और राज्यपाल में नहीं।

उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की त्रुटि, जैसे कि

इसकी उप-समिति की 2 मई, 1978 की रिपोर्ट में शामिल हैं -

यह धारणा कि राज्यपाल, शक्ति के प्रयोग में कार्य करते हुए

अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त, एक कार्यकारी कार्य का प्रयोग करता है

यह। यही कारण है कि यह इतना अधिक प्रयोग किया गया कि स्वतंत्रता

(1) [1975] 3 एस. सी. आर 365

बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

1057

न्यायपालिका का क्षरण किया जा रहा था। वह स्वतंत्रता होनी चाहिए

किसी भी कीमत पर संरक्षित, संवैधानिक यथार्थवादियों के रूप में, हम वंचित नहीं कर सकते

विधायिका या उनकी वैध विधायी शक्तियों का राज्यपाल

अनुच्छेद 309 के तहत। वह शक्ति अन्य सभी प्रावधानों के अधीन है संविधान जिसका अर्थ है कि शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है

एक तरीका जो, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की ओर ले जाएगा,

16 या अनुच्छेद 235 के पहले भाग की व्यापक सीमा। तब से

अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति निरपेक्ष या निरंकुश नहीं है, यह

उस शक्ति की वैधता का परीक्षण करना गलत होगा संभावित दुरुपयोग। विभिन्न संवैधानिक सुरक्षा उपाय एक बीमाकर्ता हैं।

इसके दुरुपयोग के खिलाफ।

आयात को उजागर करने के लिए हमारे सामने कई निर्णयों का उल्लेख किया गया था

न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने की क्षमता। यह था। उच्च न्यायालय की ओर से विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा आग्रह किया गया

कि अनुच्छेद 235 का सर्वोपरि उद्देश्य स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है

यह सुनिश्चित करके कि अधीनस्थ न्यायपालिका अछूती है कार्यकारी हस्तक्षेप से और एक बार न्यायिक की नियुक्ति से। डी.

अधिकारी बनाया जाता है, उसका बाद का करियर नियंत्रण में होना चाहिए

उच्च न्यायालय और उसे किसी भी संभावना के संपर्क में नहीं लाया जाना चाहिए

अनुचित कार्यकारी दबाव (भारत संघ बनाम. न्यायमूर्ति एस. एच. शेठ (1), कि अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण उच्च में निहित है

अनुच्छेद 235 के तहत न्यायालय प्रकृति में अनन्य, व्यापक है।

विस्तार और संचालन में प्रभावी; और यह कि कोई "द्वैत" नहीं हो सकता है

जिला न्यायालयों और उप न्यायालयों पर नियंत्रण के मामले में

क्ली 309 एक विधायी है, कार्यकारी नहीं, शक्ति और यह कि शक्ति है संविधान के सभी प्रावधानों के अधीन। अगर इस स्थिति के बावजूद

. यह, राज्यपाल का शासन-बनाने की शक्ति एक चुंबकीय बनाने की संभावना है

जिस क्षेत्र में कार्यपालक आकर्षण का केंद्र बिंदु होगा, वह

इसके लिए संविधान दोषी नहीं है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, खतरा न्यायिक स्वतंत्रता बाहर से अधिक भीतर से उत्पन्न होती है।

इस बिंदु से अलग होने से पहले, हम एक निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे।

बिहार राज्य बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। मदन मोहन प्रसाद (*) न्यायाधीश सरकारिया ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए उस मामले में कहा कि

(1) [1978] 1 एससीआर 423।

(2) [1979] 1 एससीआर 26.

✓ (3) [1976] 3 एस. सी. आर 110

एन

[1981] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58

बिहार उच्च न्यायिक सेवा की वरिष्ठता का निर्धारण

उच्च न्यायालय वैध रूप से नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद के प्रावधान के तहत किया गया। 309 संविधान का

यह। निर्णय में इस प्रश्न पर आगे चर्चा नहीं की गई है कि

इसका विस्तार से विश्लेषण करना अनावश्यक बनाता है।

इन कारणों से, हम इस तर्क को अस्वीकार करते हैं कि राज्यपाल

जिला और सत्रों की वरिष्ठता के नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है न्यायाधीश।

यह हमें दूसरे प्रश्न पर ले जाता है जो है, क्या रोटा

संबंधित को लागू करने में उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई विधि

पुष्टि और परिणामी निर्धारण के मामले में सेवा नियम

याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता बनाम प्रत्यक्ष भर्तियों से पीड़ित कोई कानूनी या संवैधानिक दुर्बलता। तर्क का मुख्य जोर

पदोन्नति पाने वालों में से, जिन्होंने पहले रिट याचिकाओं के दो सेट दायर किए हैं

हम, है कि उच्च न्यायालय द्वारा लागू रोटेशन की विधि में

पुष्टि का समय उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16। पंजाब रिट याचिका में,

याचिकाकर्ताओं ने एक वैकल्पिक याचिका दायर की है कि उनकी वरिष्ठता

द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार तय किया जाना चाहिए

9 अप्रैल, 1976 से प्रभावी। उस संशोधन द्वारा, निरंतरता की अवधि पुष्टि की तारीख की परवाह किए बिना एक संवर्ग में हमारी सेवा है

वरिष्ठता के मानदंड को नियंत्रित करना। जहाँ तक सरकार की शक्ति है

हमारे निर्णय के पूर्ववर्ती भाग द्वारा विराम दिया गया है जिसमें हमने वरिष्ठता के नियम बनाने की राज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखा है।

संक्षेप में, उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963,

जो वर्तमान में हरियाणा में लागू हैं, नियमों के समान हैं जो दिसंबर के संशोधन से पहले पंजाब में लागू थे

दिनांक 31,1976. हरियाणा के राज्यपाल ने संशोधन पेश किया था

बाद में संशोधनों को वापस ले लिया गया और मूल स्थिति जैसा कि 1963 के नियमों के तहत प्राप्त किया गया था, उसे बहाल किया गया था।

हरियाणा में अब लागू नियमों के तहत, जो लागू थे

पंजाब में 31 दिसंबर को किए गए उपरोक्त संशोधन से पहले,

1976 , ' नियम 2 (2) द्वारा 'संवर्ग पद' का अर्थ है सेवा में एक स्थायी पद।

नियम 8 (2) के तहत कैडर पदों की कुल संख्या का दो-तिहाई होना चाहिए। पदोन्नत अधिकारियों द्वारा और एक तिहाई प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा संचालित किया जाएगा।

नियम 10 (1) के तहत सीधी भर्तियों को दो के लिए परिवीक्षा पर रहना पड़ता है। वर्ष बशर्ते कि सरकार, असाधारण परिधि में

किसी भी मामले की स्थिति, परामर्श में परिवीक्षा की अवधि को कम करें बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

1

उच्च न्यायालय के साथ। परिवीक्षा को सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है और न ही उच्च न्यायालय के परामर्श से दो साल की अवधि से आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तीन साल की कुल अवधि से अधिक नहीं। नियम 10 (2) राज्यपाल को उच्च न्यायालय के परामर्श से शक्ति प्रदान करता है।

एक संवर्ग पद पर एक सीधी भर्ती की पुष्टि करने के लिए न्यायालय उस तारीख से प्रभावी है जिस तारीख को वह अवधि पूरी करता है

परिवीक्षाधीन।

नियम 12 अब हरियाणा में लागू है और जो लागू था

पंजाब में 31 दिसंबर, 1976 के संशोधन से पहले यह प्रावधान किया गया था कि सीधी भर्ती और पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता उनकी पुष्टि की संबंधित तिथियों के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

नियम 12 का परंतुक तीन प्रकार के मामलों से संबंधित है जिनमें

सेवा के स्थायी सदस्यों के पास पुष्टि की एक ही तारीख होती है। ऐसे मामलों की तीसरी श्रेणी के संबंध में, परंतुक कहता है कि पदोन्नत अधिकारियों और सीधे भर्ती होने वाले अधिकारियों के मामले में

पुष्टि की तारीख, उम्र में बड़ा छोटा से बड़ा होगा।

अधिसूचना द्वारा पंजाब में किए गए संशोधन के तहत

दिनांक 31 दिसंबर, 1976, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है

9 अप्रैल, 1976, 'कैडर पद' का अर्थ है स्थायी के साथ-साथ अस्थायी पद। सेवा में पद। जहाँ तक वरिष्ठता के नियम का संबंध है,

उपरोक्त संशोधन के तहत सदस्यों की अंतर वरिष्ठता सेवा का निर्धारण निरंतर सेवा की अवधि से किया जाना है।

पुष्टि की तारीख की परवाह किए बिना सेवा में एक पद पर।

यह स्मरणीय है कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में

वी. हरियाणा राज्य (ऊपर), यह इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम 10,

जहाँ तक वह राज्यपाल को पुष्टि की शक्ति प्रदान करता है,

खराब है क्योंकि पुष्टि की शक्ति नियंत्रण का एक हिस्सा है उच्च न्यायालय जो संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा निहित है

यह। इसलिए, अकेले उच्च न्यायालय के पास एक की पुष्टि करने की शक्ति थी

जिला और सत्र न्यायाधीश। उस निर्णय के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी 3

एक पुष्ट जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में सेवा में वापस आए।

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एकमात्र प्रावधान जिसका

उपरोक्त मामले में प्रत्यर्थी 3 द्वारा वैधता पर हमला किया गया था नियम 10 (2) में निहित एक जिसने अधिकार प्रदान किया

राज्यपाल एक सीधी भर्ती की पुष्टि करेंगे। इसमें कोई चुनौती नहीं दी गई थी

उप-नियम (2) के उस भाग के लिए जिसके लिए यह आवश्यक है कि पुष्टि

उस तारीख से बनाया जाए जो उस तारीख से पहले न हो जिस दिन प्रत्यक्ष भर्ती संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी करता है। वह हिस्सा

उप-नियम (2) अभी भी लागू है। यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि

हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स जैसा कि तब था, जो भौतिक रूप से पंजाब नियमों के नियम 12 के समान था।

जैसा कि यह अब मौजूद है और 1976 के संशोधन से संबंधित है।

;

[19

81] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

60

डॉ. चिताले, जो पदोन्नति पाने वालों की ओर से उपस्थित होते हैं

पंजाब रिट याचिका में तर्क दिया गया है कि पदोन्नति पाने वालों को धोखा नहीं दिया जा रहा है

उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायिक सेवा में पुष्टि की गई, भले ही

रिक्तियां उनके दो-तीसरे कोटे के भीतर होती हैं, जो इसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं

नियम 8 (2)। विद्वान वकील का तर्क है कि का कोटा

2/3 1/3 , जिसके लिए नियम 8 द्वारा प्रावधान किया गया है, उस समय लागू होता है।

केवल प्रारंभिक भर्ती। इसलिए कोई आदेश नहीं है,

पुष्टि करें। इस तर्क के समर्थन में, निर्भरता को एक पर रखा गया है पाँच सदस्यीय पीठ का 13 दिसंबर, 1977 का सर्वसम्मत निर्णय

नरेंद्र सिंह राव बनाम में पंजाब और हरियाणा के विद्वान न्यायाधीश।

हरियाणा राज्य (1)। उच्च न्यायालय ने उस मामले में निर्णय दिया कि नियम 8 जिसमें कोटा और नियम 12 का प्रावधान है जिसमें वरिष्ठता का नियम शामिल है।

ऋति, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कि घूर्णन का नियम नहीं कर सकता है

निहित रूप से कोटा नियम में पढ़ा जाए और प्रत्येक सदस्य

उच्च न्यायिक सेवा कड़ाई से वरिष्ठता का दावा करने का हकदार है

नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार। पदोन्नतियों ने किया है

एक बहुत मजबूत और जोरदार शिकायत है कि इस तथ्य के बावजूद कि

हरियाणा में लागू नियमों के समान, उच्च न्यायालय ने अपने प्रशासन के अभ्यास में लगातार पालन करने से इनकार कर रहा है

पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि आवेदन की कोई गुंजाइश नहीं है पुष्टि के समय घूर्णन के नियम का पालन करना बाध्यकारी है

उच्च न्यायालय एक प्रशासनिक निकाय के रूप में और इसलिए

पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता बिना किसी पद के तय की जानी चाहिए।

पुष्टि के समय रोटेशन के नियम को लागू करना।

पदोन्नति पाने वालों को होने वाली कठिनाइयों को प्रदर्शित करने के लिए,

डॉ. चिताले ने लेखन के अनुलग्नक पी-I की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है याचिका जिसे अनुलग्नक II में आगे विस्तार से बताया गया है

लिखित प्रस्तुतियाँ। ये अनुलग्नक बताते हैं, और यह विवादित नहीं है

एड, कि प्रत्यक्ष भर्तियों को पुष्टि की तारीख दी गई है जो आबंटित पुष्टि की तारीख से एक या एक दिन पहले का है

पदोन्नति देते हैं। हमारा ध्यान प्रासंगिक आदेश की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

हरियाणा अधिकारियों के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसके द्वारा

प्रत्यक्ष भर्ती, श्री एन. एस. राव को आवंटित पुष्टि की तारीख,

यह तीनों को आवंटित पुष्टि की तारीखों से केवल एक दिन पहले है पदोन्नति, भले ही बाद वाले बहुत लंबे समय तक कार्य कर रहे थे

पदोन्नतियों ने उच्च की वैधता और औचित्य दोनों पर हमला किया है 25 अगस्त, 1976 की अदालत की अधिसूचना, जिसके तहत आठ निर्देश दिए गए थे

(1) ए. आई. आर. 1978 पंजाब और हरियाणा 234.

बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

पंजाब में भर्तियों और आठ पदोन्नतियों की पुष्टि बारी-बारी से विधि लागू करके की गई थी, और सीधे भर्तियों की पुष्टि उन तारीखों से की गई थी जो पदोन्नतियों को निर्धारित की गई तारीखों से थोड़ी पहले होती हैं। पदोन्नति प्राप्त लोगों की शिकायत इस परिस्थिति से बढ़ जाती है कि 6 से 8 उत्तरदाताओं ने अपनी परिवीक्षा की सामान्य अवधि भी पूरी नहीं की थी और फिर भी उच्च न्यायालय द्वारा उनकी परिवीक्षा की अवधि को लगभग एक वर्ष और चार महीने तक कम करने के बाद उनकी पुष्टि की गई थी, बिना इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां थीं। इसके अलावा, नियम 10 (1) के परंतुक के तहत परिवीक्षा अवधि को कम करने की शक्ति राज्यपाल के पास निहित है। और यदि वह प्रावधान उन कारणों के लिए असंवैधानिक है जिनके लिए इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था

श्री एन. एस. राव (1) के मामले में कि राज्यपाल के पास कारावास की कोई शक्ति नहीं थी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत उच्च न्यायालय परिवीक्षा की अवधि को कम करने की शक्ति का दावा कर सके।

जिनके पास वरिष्ठता के नियम बनाने की शक्ति है, और अन्य प्रश्नों को प्रशासनिक रूप से उसके द्वारा तय करने के लिए छोड़ दें। दोनों पक्षों के प्रतिनिधित्व अभी भी उसके समक्ष लंबित हैं और अगर हम विवादित अधिसूचनाओं की वैधता पर निर्णय लेते हैं, तो कई व्यावहारिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं जिससे उच्च न्यायालय का वरिष्ठता तय करना मुश्किल हो सकता है। हरियाणा में, हम केवल दो अधिकारियों के बारे में चिंतित हैं-श्री बी. एस. यादव, एक प्रमोटर और श्री एन. एस. राव, एक सीधी भर्ती, क्योंकि याचिकाकर्ता 2 और 3 को इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। लेकिन उच्च न्यायालय का कहना है कि अन्य मुद्दों पर हमारे फैसले का पंजाब में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा जहां उच्च न्यायिक सेवा के कई सदस्यों के परस्पर विरोधी दावों पर विचार करने की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय पुष्टि के समय बारी-बारी से नियम लागू करके सीधे भर्ती करने वालों की तुलना में पदोन्नति पाने वालों की वरिष्ठता को रोकने के लिए अपने द्वारा अपनाई गई विधि को उचित ठहराता है। यह.

यह तर्क दिया जाता है कि इन दोनों स्रोतों से भर्ती किए गए व्यक्तियों का इस तरह से विलय किया जाना चाहिए ताकि न केवल सेवा में उनके बीच उचित अनुपात बनाए रखा जा सके, बल्कि सेवा के सदस्यों द्वारा न्याय प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के सभी संदर्भों में उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा सके। ठोस शब्दों में अनुवादित, इसका अर्थ है कि अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्य जिन्हें उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत किया जाता है और जिन्हें बार के सदस्यों में से भर्ती किया जाता है, उन्हें चयन श्रेणी में पदोन्नति के साथ-साथ उच्च न्यायालय की पीठ में पदोन्नति का भी समान अवसर होना चाहिए। जब उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती दो स्रोतों से होती है,

(1) ए. आई. आर. 1978 पंजाब और हरियाणा 234.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2

सदस्यों का उचित सम्मिश्रण सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है

सेवा और यह उस कारण से है कि कोटा नियम (जब भी

प्रत्यक्ष भर्तियाँ उपलब्ध हैं) के समय भी आवेदन करना पड़ता है

पुष्टि करें। यह सेवा के हित में नहीं होगा यदि यह था

अन्यथा, उच्च न्यायालय के अनुसार, यदि प्रत्यक्ष भर्तियां की जाती हैं

पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठता की आगे पदोन्नति की संभावनाएँ उनके नीचे। जब सीधी भर्ती की जाती है तो वे उससे बहुत कम उम्र के होते हैं

जब पदोन्नत किया जाता है। यही कारण है कि, जहाँ भी

संभव है, उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता सौंपने का दावा किया है

दूसरी ओर, प्रोमोटियों की पुष्टि की गई है और उन्हें नियुक्त किया गया है एक के बाद एक वरिष्ठता, दो से अधिक संख्या में, जब

कोई सीधी भर्ती नहीं थी। अपनी बात को स्पष्ट करने और उचित ठहराने के लिए

यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने अपने लिखित संक्षिप्त विवरण में चार अनुलग्नक संलग्न किए हैं, अनुलग्नक 'ए' से 'डी'। अनुलग्नक 'ए' सदस्यों की वरिष्ठता को दर्शाता है

से उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित और निर्धारित सेवा का

1-11-1966 , अगस्त 1976 तक और इसके साथ। सीधी भर्तियाँ होती हैं

उसमें क्रम संख्या में रखा गया है। 4 , 5 , 10 , 21 , 24 , 27 , 38 , 41 , 44 , 47 , 50 और 53. बाकी पदोन्नत हैं। न केवल, उच्च न्यायालय कहता है,

क्या यह प्रत्येक समूह के बीच बड़ी संख्या में पदोन्नति की पुष्टि करता है प्रत्यक्ष भर्तियाँ लेकिन इसने दो पदोन्नतियों को प्रत्यक्ष के बीच अंतरित किया

भर्ती। अनुलग्नक 'बी' सदस्यों की संभावित वरिष्ठता को दर्शाता है में पदों की उपलब्धता की तारीखों के संदर्भ में सेवा

कोटा नियम के अनुसार। यह प्रत्यक्ष की स्थिति को दर्शाता है

भर्ती की जाती है यदि उन्हें उस तारीख से वरिष्ठता दी जाती है जब

वे अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी करते हैं। अनुलग्नक 'सी' एक ही है

अनुलग्नक 'बी' के रूप में इस संशोधन के साथ कि यह स्थिति को दर्शाता है

प्रत्यक्ष भर्तियाँ यदि उनसे वरिष्ठता निर्धारित की जाती है

जिस तारीख से वे सेवा में शामिल हुए। अनुलग्नक 'डी' स्थिति दिखाता है

की तारीखों के अनुसार सेवा के सदस्यों का गठन

ऐसे सदस्यों के रूप में उनका निरंतर कार्यपालन। ये कथन,

उच्च न्यायालय कहता है, दिखाएगा कि उसने प्रो को वरिष्ठता सौंपी है हितों को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए तरीके से मोती और प्रत्यक्ष भर्ती

दोनों वर्ग।

जबकि पदोन्नति पाने वाले शिकायत करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया गया है

इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उच्च न्यायालय ने जवाब दिया कि उसने तराजू रखा है यहां तक कि अधिकारियों के दो वर्गों के बीच न्याय का, प्रत्यक्ष भर्ती

तर्क है कि यह वास्तव में वे हैं जिन्होंने के तहत अन्याय का सामना किया है

उच्च न्यायालय द्वारा 25 अगस्त को जारी वरिष्ठता की अधिसूचना,

1976. पंजाब रिट याचिका में 3 से 5 उत्तरदाताओं ने शिकायत की

कि उच्च न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उनकी पुष्टि नहीं की गई थी,

अर्थात् उनके परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर।

बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़; सी. जे.)

1

उच्च न्यायालय ने श्री एस. एस. सोधी के बीच दस पदोन्नति की पुष्टि की।

जो वर्तमान में उच्च न्यायालय के पंजीयक हैं, और प्रतिवादी

3 5 तक, जिससे पदोन्नति पाने वालों को उनके कार्यालय का लाभ दिया जाता है

यह पुष्टि के समय लागू किया जाता है। वे वैधता पर हमला करते हैं संशोधित नियम 12, जो पंजाब में लागू है, जमीनी स्तर पर

कि नियम कि वरिष्ठता निरंतरता की तारीख पर निर्भर होनी चाहिए

किसी भी पद पर कार्य करना न तो उचित है और न ही उचित है। वे भी

पंजाब के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दें

31 दिसंबर, 1976 इस आधार पर कि इसे पूर्वव्यापी दिया गया था

9 अप्रैल, 1976 से मनमाने ढंग से प्रभाव, केवल एक दृष्टिकोण के साथ

उच्च न्यायालय द्वारा 25 अगस्त को जारी वरिष्ठता की अधिसूचना,

1976. वैकल्पिक रूप से, उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि यदि अवधि

उनकी परिवीक्षा की अवधि को कार्यपालन की अवधि के खिलाफ तौलना होगा।

पदोन्नति पाने वालों की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जिस दिन

पदोन्नति अधिकारी एक स्थायी रिक्ति के खिलाफ कार्य करना शुरू करता है

अपने कोटे में उपलब्ध है।

इन विवादों के आलोक में, संकल्प का प्रश्न

क्या पुष्टि का तरीका उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया है

2 के अनुपात में पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों के आवर्तन द्वारा: 1

प्रासंगिक नियमों की उचित व्याख्या पर उचित ठहराया जाता है। यह है कि

नियम 8 का संचालन प्रारंभिक भर्ती के चरण तक सीमित

पुष्टि के स्तर पर भी? ये हैं सवाल हमारे विचार के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

नियम 8, जैसा कि इसके शीर्ष से ही पता चलता है, एक विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है।

एक विशिष्ट समय बिंदु के संदर्भ में सेवा की स्थिति, अर्थात्ः

* सेवा में भर्ती '। "सीधे भरे जाने वाले शब्द"

भर्ती "जो नियम 8 के उप-नियम (2) के प्रावधान में होती है

यह भी इंगित करें कि इस उप-नियम का संचालन कोन है

पदोन्नति या बार से सीधी नियुक्ति द्वारा। नियम 10,11 और 12 परिवीक्षा के विनियमन, प्रत्यावर्तन के लिए प्रावधान करता है

पदोन्नत अधिकारी और वरिष्ठता, सेवा की कौन सी शर्तें हैं

नियम में वर्णित 'सेवा में भर्ती' से अलग और अलग

8. दूसरे शब्दों में, नियम 8 केवल भर्तियों का संबंधित कोटा तय करता है।

(1) . इस तरह के आरक्षण का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर किया जाना है। केवल नियुक्तियाँ, कुल पदों की संख्या का दो तिहाई आरक्षित करके

संवर्ग में पदोन्नतों के लिए और 1/3 सीधे भर्ती के लिए।

ऐसा

लगता है [1981] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे लिए यह स्पष्ट है कि एक पद जो पदोन्नति के कोटे में खाली पड़ता है

इसमें प्रत्यक्ष भर्ती की पुष्टि से भरा नहीं जा सकता है और न ही वास्तव में किसी ऐसे पद पर पदोन्नति की पुष्टि की जा सकती है जो प्रत्यक्ष भर्ती के कोटे के भीतर हो।

यदि यह नियम 8 का सही निर्माण है, तो कन्फ़ायर की विधि

प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के आवर्तन द्वारा मिलान, चाहे जो भी हो

क्या विशेष अधिकारी को दी गई रिक्ति इसके अंतर्गत आती है

जिस वर्ग से वह संबंधित है, उसका कोटा इसके उल्लंघन में होगा

वह नियम। यह इस न्यायालय द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आयोजित किया गया था।

न्यायालय बनाम। हरियाणा राज्य (सुप्रा) ने कहा कि 'नियुक्ति' निरंतर नहीं है।

अनावश्यक प्रक्रिया, कि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाए

एक व्यक्ति के रूप में शुरू में या तो पदोन्नति द्वारा सेवा में भर्ती किया जाता है

या सीधी भर्ती द्वारा और वह पुष्टि इसका हिस्सा नहीं है

नियुक्ति की प्रक्रिया। भर्ती का इलाज करने की आवश्यकता

सेवा 'और' पुष्टि 'दो अलग-अलग मामलों के रूप में

इसकी सराहना तभी की जा सकती है जब यह महसूस किया जाए कि 'भर्ती के लिए

'सेवा' एक ऐसा मामला है जो राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत आता है।

अनुच्छेद 233 के तहत जबकि 'पुष्टि' नियंत्रण का विषय है '

अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय में निहित होना। सुपरइम्पोजिशन

इसलिए पुष्टि और वरिष्ठता से संबंधित नियम इसके विपरीत हैं - न्यायिक सेवा को नियंत्रित करने वाली बुनियादी संवैधानिक अवधारणाएँ।

इसके अलावा, कन्फिर के चरण में रोटा प्रणाली का अनुप्रयोग

मिलन व्यावहारिक कठिनाइयों से घिरा हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि रिक्तियां हैं प्रत्यक्ष भर्तियों के कोटे में 2 या 3 साल के लिए नहीं भरा जा सकता है

असामान्य कारण नहीं है कि प्रत्यक्ष भर्तियां उपलब्ध नहीं हैं, और

उस अवधि के दौरान पदोन्नति के कोटे में कई रिक्तियां होती हैं।

जो दो या तीन वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, कर सकते हैं

ऐसे पदोन्नतियों की पुष्टि को स्थगित करना

उनके कोटे में रिक्त पद, जब तक कि सीधी भर्तियां नियुक्त नहीं की जाती हैं

और निर्धारित कार्य पूरा करने पर पुष्टि के लिए पात्र हो जाते हैं।

परिवीक्षा की अवधि, किसी भी उचित आधार पर उचित ठहराया जाए? है ना?

पदोन्नति पाने वालों की पुष्टि को केवल स्थगित करना उचित और उचित है।

क्योंकि प्रत्यक्ष भर्तियाँ उस समय उपलब्ध नहीं हैं ताकि

ताकि उच्च न्यायालय दोनों स्रोतों से पुष्टि कर सके

बारी-बारी से? ठीक यही उच्च न्यायालय ने किया है। विवादित अधिसूचना दिनांकित 25-8-1976 और यही कारण है

उसने पंजाब में दस और पदोन्नतियों की पुष्टि क्यों नहीं की, जिनके लिए

पदोन्नति के कोटे के भीतर रिक्तियां उपलब्ध हैं।

ए. के. सुब्रमण्यन बनाम भारत संघ, (1) विपक्ष का विवाद

विचार करता है कि इसमें शामिल एक निहित घूर्णन प्रणाली है

(1) [1975] 2 एससीआर 979।

बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

10

कोटा नियम और इसलिए कोटा नियम को पुष्टि के चरण में भी लागू किया जाना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह सच है कि उस मामले में यह देखा गया था कि जब भर्ती दो या दो से अधिक स्रोतों से होती है, तो कोटा प्रणाली शुरू करने और बारी-बारी से इसे लागू करने में कोई अंतर्निहित अयोग्यता नहीं होती है। लेकिन यह वह प्रश्न नहीं है जिस पर हमें अपने समक्ष रिट याचिकाओं में विचार करना है। न्यायालय का निर्णय (पृष्ठ 994) प्रासंगिक है कि आरक्षण नियम प्रारंभिक भर्ती के समय लागू किया जाएगा न कि पुष्टि के समय। न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति और पुष्टि के उद्देश्यों के लिए आवेदन किए जाने वाले परीक्षण पूरी तरह से अलग हैं क्योंकि 'पदोन्नति' और 'पुष्टि' के बीच एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अंतर है।

एन. के. चौहान बनाम गुजरात राज्य, (1) इसे दोहराया गया था (पृष्ठ)

1051—1053) कि इस न्यायालय के हाल के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए,

यह नहीं माना जा सकता था कि 'कोटा' 'रोटा' के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि

जहाँ पूर्व को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, बाद वाले को निहित रूप से लिखा गया है। एड। हममें से एक, कृष्ण अय्यर, जे., निष्कर्षों का सारांश देते हुए

न्यायालय ने कहा:

" कोटा नियम, अनिवार्य रूप से, आवेदन का आह्वान नहीं करता है रोटा नियम। इस स्थिति का प्रभाव यह है कि यदि पर्याप्त है

प्रत्यक्ष भर्तियों की संख्या आने वाली नहीं है

1960 के बाद से उनके और उन लोगों के कारण होने वाले अनुपात को भरने के लिए

वर्तमान रिक्तियों को पदोन्नतियों द्वारा भरा गया है, बाद में प्रत्यक्ष

भर्तियां वरिष्ठता के लिए नियुक्ति की 'मानित' तिथियों का दावा नहीं कर सकती हैं

उस समय से सेवा में, रोटे के अनुसार या

बारी-बारी से, सीधी भर्तियां 'रिक्तियां' पैदा हुईं।

इस निर्णय के अनुसार पदोन्नति पाने वालों की वरिष्ठता को परेशान नहीं किया जा सकता है

खुले बाजार से बाद में आने वाले लोगों द्वारा, इस हद तक बचत करें कि

किसी भी अतिरिक्त पदोन्नति को कम करना होगा।

परमजीत सिंह संधू बनाम। राम रखा, (2) यह इस द्वारा आयोजित किया गया था

नियम 3,4,6,8 और 10 के सामंजस्यपूर्ण पठन पर न्यायालय

पंजाब पुलिस नियम, 1959 में कहा गया है कि आरक्षण नियम दोनों लागू थे।

प्रारंभिक भर्ती के समय और पुष्टि के समय।

हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह मामला प्राधिकरण के लिए नहीं है

प्रस्ताव है कि जब भी सेवा नियम कोटा प्रदान करते हैं, तो नियम

कि कोटा और रोटे के नियम सह-अस्तित्व में नहीं हो सकते। सेवा नियम हो सकते हैं तो प्रदान करें या वे इस तरह की व्याख्या को मान सकते हैं। उस में

घटना, उनकी वैधता की कुल सेटिंग में परीक्षण किया जाना हो सकता है

(1) [1977] 1 एससीआर 1037।

(2) [1979] 3 एससीआर 584।

[198

1] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6

तथ्य। इसलिए, क्या कोटा प्रणाली का पालन नहीं करना है

केवल प्रारंभिक भर्ती के स्तर पर, लेकिन समापन के स्तर पर भी मैशन अमूर्त कानून का मामला नहीं है, बल्कि यह शब्द पर निर्भर करेगा।

विचाराधीन नियमों और नियमों की योजना का निर्धारण।

किसी भी तरह का हठधर्मी दावा करना, एक या दूसरे तरीके से, गलत है।

इन अधिकारियों की समीक्षा पर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि

पंजाब को नियंत्रित करने वाले नियमों की उचित व्याख्या पर और

हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस, रोटे के नियम को पढ़ा नहीं जा सकता

कोटा के नियम में। दूसरे शब्दों में, 2 का अनुपातः 1 होगा।

भर्ती के चरण में आवेदन किया जाना है लेकिन भाषा पर नहीं किया जा सकता है

संबंधित नियमों को पुष्टि के चरण में लागू किया जाए।

हमारी राय में, इसलिए, उच्च न्यायालय में उचित नहीं था

मेम की पुष्टि के समय रोटेशन के नियम को लागू करना

हम यह याद दिलाना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय के पाँच विद्वान न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ पंजाब और हरियाणा की अदालत ने खुद 13 दिसंबर, 1977 को फैसला सुनाया था।

एन. एस. राव बनाम हरियाणा राज्य, (ऊपर) कि रोटा का शासन नहीं हो सकता है पंजाब के नियम 8 द्वारा निर्धारित कोटा के नियम में पढ़ा जाए।

उच्च न्यायिक सेवा नियम। यह विशेष द्वारा देखा गया था

अपने फैसले के पैराग्राफ 14 में पीठ ने कहा कि नियम का एक सादा अध्ययन

8 यह दर्शाता है कि नियमों के निर्माताओं का इरादा केवल

आरक्षण का प्रावधान करें और यह कि कोई संकेत नहीं दिया गया है कि

कन्फ़ायर के समय भी घूर्णन प्रणाली का पालन करना पड़ता था

विवाह या वरिष्ठता तय करने के उद्देश्य से। इस पर आते हुए

निष्कर्ष, उच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर भरोसा रखा

ए. के. सुब्रमण्यम और एन. के. चौहान की अदालत, जिसके लिए हमारे पास अन्य मामले हैं।

तैयार संदर्भित। उच्च न्यायालय ने पैरा में अपना निष्कर्ष व्यक्त किया

निर्णय का ग्राफ 22 यह कहते हुए कि नियम 8 और 22 स्वतंत्र हैं

कि घूर्णन प्रणाली निहित रूप से नहीं हो सकती है

नियम 8 द्वारा निर्धारित कोटा नियम को पढ़ें और यह कि सदस्य

उच्च न्यायिक सेवा के लोग वरिष्ठता का दावा करने के हकदार हैं, सख्ती से

नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार। हम असमर्थ हैं

यह समझें कि अपने प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में,

उच्च न्यायालय अपने स्वयं के विशेष निर्णय का पालन करने में विफल हो सकता था

पाँच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ। हमारा मानना है कि

उपरोक्त निर्णय ने मामले पर सही दृष्टिकोण लिया है

नियम 8 और 12 का संयुक्त अध्ययन।

हम दोहराव की कीमत पर कहना चाहेंगे कि हम नहीं हैं

इस अमूर्त प्रश्न से निपटने के लिए कि क्या कोटा का नियम

आवश्यक रूप से घूर्णन के नियम को बाहर करता है। हम केवल चिंतित हैं।

यह इंगित करने के लिए कि यह कहना सही नहीं है कि रोटे का नियम बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.) होना चाहिए।

अनिवार्य रूप से कोटा के नियम में पढ़ा जाना चाहिए। हमें उन मामलों में इस संकीर्ण प्रश्न का निर्णय करना होगा कि क्या उच्च न्यायिक सेवा नियमों के नियम 8 और 12 की सही व्याख्या पर

पंजाब और हरियाणा, नियम 8 द्वारा निर्धारित कोटा नियम पुष्टि के समय इसके विस्तार को उचित ठहराता है, ताकि हर दो पदोन्नति की पुष्टि होने के बाद एक सीधी भर्ती की पुष्टि की जा सके और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक पदोन्नति की पुष्टि नहीं की जा सकती है, भले ही रिक्तियां उनके कोटे के भीतर उपलब्ध हों जिसमें उनकी पुष्टि की जा सकती हो। नियमों की उचित व्याख्या पर हमारी राय है कि पदोन्नत व्यक्ति उन रिक्तियों में पुष्टि के हकदार हैं जो उनके दो तिहाई कोटे के भीतर उपलब्ध हैं, चाहे एक तिहाई रिक्तियों पर पुष्टि की गई सीधी भर्तियां हों या न हों। और समान रूप से, प्रत्यक्ष भर्तियां उन रिक्तियों में पुष्टि की जाने की हकदार हैं जो उनके 1/3 के कोटे के भीतर उपलब्ध हैं, चाहे 2/3 रिक्तियों पर पुष्टि किए गए पदोन्नतियों का कब्जा हो या न हो। हम जिस बात के औचित्य में कमी पाते हैं, वह यह है कि उच्च न्यायालय ने पदोन्नतियों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है, भले ही उनके कोटे में रिक्तियां उपलब्ध हों, जिसमें उन्हें केवल इसलिए सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि ऐसा करने से, एक समय में दो से अधिक पदोन्नतियों की पुष्टि करनी पड़ सकती है, बिना किसी प्रोपोर की पुष्टि के।

प्रत्यक्ष भर्तियों की संख्या। अनुच्छेद 14 और 16 में जो निष्पक्षता प्रतिपादित की गई है, वह यह है कि यदि कोई प्रवर्तक अन्यथा कन्फर्म के लिए उपयुक्त है।

पदोन्नति के कोटे के भीतर आने वाली एक रिक्ति उपलब्ध है जिसमें उसकी पुष्टि की जा सकती है, उसकी पुष्टि तब तक स्थगित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि एक सीधी भर्ती, चाहे वह अभी तक नियुक्त हो या न हो, उसकी परिवीक्षा की अवधि को समाप्त नहीं कर देती है और उसके बाद पुष्टि के लिए पात्र हो जाती है। समझौते के मामले में इस सिद्धांत को अपनाने से, व्यवहार में, पदोन्नति पाने वालों को कोई अनुचित लाभ नहीं मिलेगा। उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए तथ्य और आंकड़े

1979 के डब्ल्यू. पी. 266 में अपने जवाबी-हलफनामे के अनुलग्नक आर-4 से पता चलता है कि पदोन्नति के कोटे में रिक्तियां आम तौर पर तब तक उपलब्ध नहीं होती हैं जब तक कि पदोन्नति पाने वाले कार्यवाहक जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में दो से पांच साल की सेवा में नहीं होते हैं।

जहाँ तक उत्तरदाता 6,7 और 8 की पुष्टि की गई है, उच्च न्यायालय के पंजीयक द्वारा अपने लेख में निर्धारित तथ्य

जवाबी हलफनामा, हमारी राय में, "असाधारण परिस्थितियों" का गठन नहीं करता है जैसे कि उनकी परिवीक्षा की सामान्य अवधि पूरी करने से बहुत पहले उनकी पुष्टि को सही ठहराने के लिए। यह याद किया जा सकता है कि प्रत्येक ने लगभग एक वर्ष और चार महीने की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के बाद उनकी पुष्टि की थी। दो साल की उनकी सामान्य परिवीक्षा अवधि में कमी को उचित ठहराने वाली असाधारण परिस्थितियों के अभाव में, हम खुद को उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ पाते हैं जिसके द्वारा इन तीन उत्तरदाताओं की पुष्टि सामान्य रूप से [1981] 1 एस. सी. आर. के लिए देय होने से पहले की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुष्टि करें। आदेश स्पष्ट रूप से गारंटी का उल्लंघन है

समान अवसर, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पूर्वाग्रहग्रस्त हैं, और होना चाहिए

इस कारण से अलग कर दिया जाए।

उच्च न्यायालय अब उनकी पुष्टि करने के लिए स्वतंत्र होगा।

उस तारीख या तारीख से प्रभाव जिस पर उन्होंने अपना सामान्य कार्य पूरा किया

उच्च न्यायालय की संतुष्टि के लिए परिवीक्षा की अवधि। यह है।

इस सवाल के अलावा कि क्या उच्च न्यायालय अभ्यास कर सकता है वह शक्ति जो नियम 10 (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त की गई थी

राज्यपाल। परंतुक द्वारा सरकार को प्रदत्त शक्ति

न ही यह प्रत्यक्ष रूप से बुरा है क्योंकि ऐसी शक्ति सीधे उस पर प्रभाव डालती है।

संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण यह। यदि कोई भी प्राधिकरण ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो यह है

उच्च न्यायालय, राज्यपाल नहीं। हम सीमित के लिए मान रहे हैं इन याचिकाओं का उद्देश्य कि उच्च न्यायालय, अपवादात्मक रूप से

राज्यपाल के पास पुष्टि करने की शक्ति नहीं है, कि सामान्य प्रत्यक्ष भर्तियों की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष है और जब तक कि

प्रत्येक व्यक्तिगत मामले से जुड़ी असाधारण परिस्थितियाँ हैं,

एक सीधी भर्ती की पुष्टि उससे पहले की तारीख से नहीं की जा सकती है

तारीख जिस पर उसने दो की अपनी परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है वर्षों से। उच्च न्यायालय परिवीक्षा की कोई भी अवधि तय करने के लिए स्वतंत्र नहीं है।

जैसा कि वह अपनी इच्छानुसार दो वर्ष की अवधि को पसंद करता है या कम करता है और

आनंद मिलता है।

पंजाब में लागू संशोधित नियम 12 में कहा गया है कि

मार्गदर्शक मानदंड के रूप में कैडर पद में निरंतर सेवा की अवधि

वरिष्ठता तय करने के लिए। उस नियम को राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया था

31 दिसंबर, 1976 और 9 अप्रैल से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया।

1976. चूँकि राज्यपाल के अधीन विधायी शक्ति का प्रयोग किया जाता है

मामला। वर्तमान मामले में इस तरह की कोई सांठगांठ नहीं दिखाई गई है राज्य सरकार। इसके विपरीत, यह हमें प्रतीत होता है कि रेट्रो

9 अप्रैल, 1976 से नियमों को केवल देखने के लिए प्रभाव दिया गया था।

कारण यह है कि 25 अगस्त, 1976 को उच्च न्यायालय ने एक अधिसूचना जारी की थी नियुक्त पदोन्नतियों और प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता तय करना

पंजाब की उच्च न्यायिक सेवा के लिए। अधिसूचना जारी की गई

31 दिसंबर, 1976 को राज्यपाल द्वारा, इसलिए, कार्य करेगा भविष्य में नियुक्तियाँ या पदोन्नति उस तारीख के बाद की जाती हैं न कि बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.) को।

1 पामतक

उस तारीख से पहले की गई नियुक्तियाँ या पदोन्नति। की वरिष्ठता

पुष्टि की तारीखों के मानदंड के अनुसार न्यायालय, बिना घूर्णन के नियम को लागू करना। पदोन्नत लोगों की वरिष्ठता या

31 दिसंबर, 1976 के बाद नियुक्तियों का निर्धारण तदनुसार किया जाएगा।

उस तारीख की अधिसूचना के तहत घोषित नियमों के साथ। में।

पंजाब रिट याचिका के अनुलग्नक पी-I में, अर्थात श्री जे. एस. चठा और श्री हरदेव सिंह को नियुक्त किया गया।

या 31 दिसंबर, 1976 से पहले पदोन्नत किया गया। क्रम संख्या 37 के लोग

क्रम संख्या 43, जो श्री जी. एस. कालरा से शुरू होता है और

31 दिसंबर, 1976। दिसंबर की अधिसूचना की वैधता 31 से, 1976 को हमारे सामने गंभीर रूप से चुनौती नहीं दी गई थी, इसके अलावा

पूर्वावलोकन। हम कोई संवैधानिक या कानूनी भी नहीं देखते हैं। निरंतर कार्यपालन की परीक्षा के लिए आपत्ति जिससे शुरू की गई।

जहाँ तक हरियाणा रिट याचिकाओं का संबंध है, वे

केवल दो अधिकारियों के बीच वास्तव में वरिष्ठता का प्रश्न शामिल है,

अर्थात्, श्री बी. एस. यादव, जो एक प्रवर्तक हैं और श्री एन. एस. राव, जो एक सीधी भर्ती है। अन्य दो पदोन्नत करते हैं, अर्थात्, पेटी

2 और 3, को विचाराधीनता के दौरान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया है इस न्यायालय में रिट याचिकाओं की। नियम 12, जो लागू नहीं है

हरियाणा में, नियम 12 के समान है जो पहले पंजाब में लागू था।

31 दिसंबर, 1976 को इसके संशोधन के लिए। नियम 12, जैसा कि मूल रूप से था अस्तित्व में था, 21 अप्रैल को हरियाणा के राज्यपाल द्वारा संशोधित किया गया था

1972 1 अप्रैल, 1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। हालांकि,

2 सितंबर, 1977 को राज्यपाल ने उस संशोधन को फिर से रद्द कर दिया।

1 अप्रैल, 1970 से प्रभावी, और वरिष्ठता के नियम को बहाल किया

यह मूल रूप से 1963 के नियमों में मौजूद था। इसलिए हरियाणा में

बिना पुष्टि की तारीखों के संदर्भ में निर्धारित किया गया नियम या आवर्तन को लागू करना।

जिस तरह से नियम बनाए गए हैं, हमें उस पर अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए

राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायिक सेवा में संशोधन किया गया है

पंजाब और विशेष रूप से हरियाणा के राज्यपाल द्वारा। पंजाब में,

इस सवाल पर उच्च न्यायालय से कभी सलाह नहीं ली गई कि क्या

31 दिसंबर, 1976 को किए गए संशोधनों को पूर्वव्यापी दिया जाना चाहिए।

सक्रिय प्रभाव और, यदि हां, तो किस तारीख से। किए गए हैं संशोधन

उच्च न्यायालय के विरोध के बावजूद। हरियाणा में, संशोधन

21 अप्रैल, 1972 को केवल एक न्यायिक व्यवस्था के बावजूद बनाया गया था।

अधिकारी जो एक सीधी भर्ती है। सौभाग्य से, वह संशोधन था

2 सितंबर, 1977 को उत्तराधिकारी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

0

1 अप्रैल से उस संशोधन को लंबे समय तक पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था।

1970 क्योंकि 21 अप्रैल, 1972 के संशोधन को पूर्वव्यापी दिया गया था

1 अप्रैल, 1970 से प्रभावी और उस संशोधन को प्रभावी होना था

सेवा नियमों में संशोधन की आवश्यकता पर अपने दिमाग को अधिक बारीकी से लागू करें उच्च न्यायपालिका और नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी

बहुत बार। यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि पूर्वव्यापी प्रभाव देना

नियमों के कारण निराशा और असंतोष पैदा होता है क्योंकि न्यायपूर्ण

अधिकारियों की अपेक्षाएँ झूठी हैं। इस प्रकार तय की गई वरिष्ठता है

अस्थिर, पेशेवरों के बीच लंबे समय तक चलने वाले मुकदमेबाजी को जन्म देते हुए मोती और प्रत्यक्ष नियुक्तियां। यह अनुशासनहीनता को जन्म देता है और आकर्षित करता है

उच्च न्यायालय अखाड़े में, जिसे पदच्युत किया जाना है।

पंजाब और हरियाणा में एक विचित्र समस्या है क्योंकि उनके पास है

एक आम उच्च न्यायालय। लेकिन वे धन्य हैं, शापित नहीं, एक के साथ

सामान्य उच्च न्यायालय। आज हम विचित्र दृश्य देखते हैं उच्च न्यायालय को अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए बुलाया जा रहा है

एक राज्य में एक परीक्षा द्वारा और दूसरे राज्य में अधिकारियों की एक परीक्षा द्वारा

विपरीत परीक्षण। पंजाब में, में एक पद पर निरंतर कार्यपालन

सेवा वरिष्ठता की कसौटी है। हरियाणा में, समापन की तारीख

संकरण शासी कारक है। क्या दोनों राज्यपाल नहीं आ सकते हैं?

एक साथ और वरिष्ठता की एक समान परीक्षा को लागू करते हुए एक संयुक्त निर्णय लें

उनके न्यायिक अधिकारियों के लिए जो एक सामान्य उच्च न्यायालय के अधीन हैं? और हालांकि यह अनुच्छेद 309 के परंतुक की आवश्यकता नहीं है

संविधान में, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी संशोधन हो रहे हैं

इसके बाद बनाए जाने वाले नियमों को परामर्श से बनाया जाएगा -

उच्च न्यायालय। इससे कुछ भी नहीं खोएगा और बहुत कुछ है। हासिल करने के लिए: सद्भावना, विशेषज्ञ सलाह और अनुभव का लाभ

एक निकाय का जिस पर नियंत्रण के बाद से नियमों का प्रशासन करना पड़ता है अनुच्छेद 235 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय इसमें निहित हैं। यह दुखद है कि

पदोन्नति और प्रत्यक्ष भर्तियों को अपना समय बर्बाद करना पड़ता है और

मुकदमेबाजी में ऊर्जा जो वे वहन नहीं कर सकते हैं और जो काफी हद तक उत्पन्न होती है

उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच समन्वय की कमी के कारण

राज्य सरकारें। यह एक नया पत्ता मोड़ने का समय है।

परिणामस्वरूप, हम 1979 की रिट याचिका 266 को आंशिक रूप से अनुमति देते हैं, जिसे रद्द कर दिया जाता है।

पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित उच्च न्यायालय का दिनांक 3 सितंबर, 1976; (ii) वह आदेश जिसके द्वारा उत्तरदाता 6,7

और उनकी परिवीक्षा की अवधि को कम करके 8 की पुष्टि की गई; और

(iii) प्रोमो की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के बाद के सभी आदेश

टी और बारी-बारी से सीधी भर्ती। हम निर्देश देते हैं कि:

(क) उच्च न्यायालय संबंधित मामलों को संशोधित और संशोधित करेगा।

याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं की पुष्टि की तारीखें 3 से

11 , आवर्तन के नियम को लागू किए बिना; बी. एस. यादव वी. हरियाणा (चंद्रचूड़, सी. जे.)

(i) याचिकाकर्ता, यदि वे अन्यथा अनुबंध के लिए उपयुक्त हैं, तो कोटा में उनके लिए रिक्तियां उपलब्ध होने की तारीखों से उनकी पुष्टि की जाएगी।

पदोन्नति;

((ii) 3 से 11 तक के उत्तरदाताओं की प्रत्यक्ष भर्तियों के कोटे में आने वाले रिक्त पदों के खिलाफ पुष्टि की जाएगी, जो उन तारीखों से प्रभावी होगी जब उन्होंने अपनी दो साल की परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की थी। चूंकि परिवीक्षा की सामान्य अवधि को तब तक कम नहीं किया जा सकता है जब तक कि उच्च न्यायालय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में संतुष्ट न हो कि

" असाधारण परिस्थितियां उस अवधि में कमी को उचित ठहराती हैं, और चूंकि उच्च न्यायालय ने कुछ उत्तरदाताओं की परिवीक्षा अवधि को कम करते हुए ऐसे कारण नहीं दिए थे, इसलिए उत्तरदाताओं 3 से 11 की पुष्टि की जाएगी जैसा कि ऊपर कहा गया है। उनकी परिवीक्षा अवधि।

(ख) उच्च न्यायालय अंतर वरिष्ठता को फिर से तैयार करेगा -

(i) ऐसे याचिकाकर्ताओं और प्रत्यर्थियों में से जिन्हें 31 दिसंबर, 1976 से पहले उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नत या नियुक्त किया गया था, उपरोक्त निर्देश (ए) के अनुपालन में उन्हें आवंटित पुष्टि की संबंधित तिथियों के आधार पर; और

((ii) ऐसे याचिकाकर्ताओं, प्रत्यर्थियों और अन्य लोगों की, जिन्हें संशोधित अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर, 1976 को या उसके बाद सेवा में किसी पद पर नियुक्त किया गया था।

नियम 12.

(ग) उच्च न्यायालय चयन श्रेणी में पदोन्नति और उसके द्वारा दिए गए अन्य संबद्ध आदेशों की समीक्षा और पुनर्विचार करेगा।

इन निर्देशों और उन पर तय की जाने वाली वरिष्ठता के संबंध में

इसका आधार। उच्च न्यायालय आवश्यक समायोजन करेगा।

और उसमें किए जाने वाले परिवर्तन, की जाने वाली कार्रवाई के आलोक में

उपरोक्त निर्देशों (ए) और (बी) के अनुपालन में। द.

उच्च द्वारा पारित पुष्टि, पदोन्नति और अन्य आदेश

इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान न्यायालय के अनुसार,

इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश, परिणाम के अधीन

इन रिट याचिकाओं में से। 1978 की 4228 से 4230 तक की रिट याचिकाओं की भी आंशिक रूप से अनुमति है।

उन्होंने 1979 की रिट याचिका संख्या 266 के समान विस्तार किया। द हाई

आर. टी. याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी की वरिष्ठता को फिर से समायोजित करेगा।

3 उसमें उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करके और

हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1963 [1981] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो 1 अप्रैल, 1970 को या उससे प्रभावी था। वरिष्ठता सूची उच्च न्यायालय द्वारा आवर्तन के नियम को लागू किए बिना और पंजाब रिट याचिका में हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में पुष्टि की तारीखों के आधार पर तैयार की जाएगी। उच्च न्यायालय चयन श्रेणी में पदोन्नति की समीक्षा और परिणामी आदेशों के संबंध में दिए गए अन्य निर्देशों का भी पालन करेगा।

पंजाब से उपरोक्त रिट याचिकाओं में ये निर्देश और

हरियाणा का जल्द से जल्द अनुपालन किया जाएगा, अधिमानतः आज से तीन महीने की अवधि के भीतर।

पार्टियाँ अपना खर्च खुद वहन करेंगी।

याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

पी बी आर।